EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By- Nikhil Ranjan
Useful For Prelims
Date: 15 December 2025

भाषा विमर्श

बुद्धिनाथ मिश्र
देहरादून, उत्तराखंड

असुंदर से सुंदर शब्दों की ओर...

भाषा की यात्रा क्रूर से कोमल और असुंदर से सुंदर की ओर होती है। जानें शौच की क्रिया और उसके स्थल के लिए किन-किन शब्दों का उपयोग क्रमशः हुआ...

बचपन में जब मैं अपने मैथिलीभाषी गांव में बड़े-बुजुर्गों से शौच के लिए बाहर जाने के लिए 'नदी दिस' (नदी की ओर) जाना सुनता था, तब उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझता था। बाद में पता चला कि उसी क्रिया के लिए वहां 'पोखरि दिस' (पोखरे की ओर) जाना, जलाशय जाना आदि भी कहते हैं। मतलब 'मल त्याग' जैसी असुंदर क्रिया को नदी-पोखर या जलाशय की ओर जाना कहा गया, क्योंकि वहां जाकर शौच के अलावा मिट्टी से हाथ और लोटा मलना और आचमन करना भी शामिल था। गांवों में नागर सभ्यता आने से पहले स्त्री-पुरुष दोनों के लिए यही व्यवस्था थी, जिसे बनारस के लोग 'बाहरी अलंग' कहते हैं। जमींदारी नजाकत ने शौचालय को जन्म दिया। यानी शौच करने का घर। गांवों में इसका आविष्कार मुख्यतः स्त्रियों की आबरू के मद्देनजर हुआ। देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इस क्रिया के लिए भिन्न-भिन्न प्रतीकात्मक नाम हैं।

आजाद भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी को कैसे औपनिवेशिक भाषा अंग्रेजी की दासी बना दिया गया है, इसका नमूना रेलवे स्टेशनों पर दिखता रहा है। वहां बहुत पहले अंग्रेजी में 'लैट्रिन' होता था और हिंदी में 'पैखाना'। फिर अंग्रेजी में 'टायलेट' हुआ तो उसकी नकल में हिंदी में 'प्रसाधन' कर दिया गया। अंग्रेजी कुछ और कुलीन होकर 'पब्लिक सर्विसेज' लिखने लगी, तो हिंदी के सिपाही भी पीछे क्यों रहते! उन्होंने चट से उसे 'जन सुविधाएं' कर दिया! जबकि एक अकेला 'शौचालय' शब्द हमारे लिए पर्याप्त था। मुझे डर है कि इधर 'वाशरूम' के चलन की देखा-देखी हिंदी में 'धौतालय' जैसा शब्द न बना लिया जाए। बड़े होटलों, हवाई अड्डे आदि संभ्रांत स्थानों पर तो अमेरिकी शब्द 'रेस्टरूम' आ गया है, यानी सीधे 'विश्रामालय'!

वैसे, गौर करिए तो अंग्रेजी में शौचालय के लिए अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग शब्द हैं। विमानों में इसके लिए रोमन में 'डब्ल्यू सी' लिखा होता है, जिसका फुल फार्म 'वाटर क्लोजेट' है। यह भी पुराने 'लैट्रिन' जैसा ही अर्थ देता है। कहीं-कहीं रोमन में 'सीआर' भी लिखा होता है, जो फिलिपीन के 'कंफोर्ट रूम' का संक्षिप्त रूप है। ऐसे ही एक पुराना शब्द 'लैवेटरी' भी है, जो ट्रेनों, विमानों, जहाजों में लिखा जाता था। पानी के जहाजों में शौचालय आगे होता है, इसलिए वहां शौचालय को 'हेड' कहते हैं। शौचालय के लिए 'बाथरूम' तो आज भी सर्वाधिक प्रचलित है, जबकि वह स्नान घर है। यह अलग बात है कि प्रायः स्नान घरों में शौच की व्यवस्था रखी ही जाती है। संस्कृत में इस क्रिया के लिए बहुप्रचलित शब्द है 'शंका' जो दो प्रकार की होती हैं -लघुशंका और दीर्घशंका। लघुशंका का ही छोटा रूप लघ्वी है, जो मैथिली में लघ्घी हो गई है। आजकल कमोड पर बैठकर त्याग-सुख लेना राजगद्दी से कम नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी में शौचालय को 'थ्रोन' भी कहते हैं!

भाषा की विकास-यात्रा क्रूर से कोमल और असुंदर से सुंदर शब्दों की ओर होती रही है। तभी लोगों ने 'झाड़ा फिरना' जैसा क्रूर शब्द न बोलकर संकेतों में 'नदी दिस' जाना बोला।

buddhinathji@gmail.com

संगीतायन

पंडित लक्ष्मण कृष्णराव
दिल्ली

शास्त्रीय संगीत का यशस्वी मंच

तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में हर वर्ष आयोजित होता है। इस साल 101वां समारोह आज से आरंभ से रहा है, जो 19 दिसंबर तक ग्वालियर में आयोजित होगा। इस समारोह और उसकी कुछ स्मृतियों पर एक दृष्टि...

संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति को अक्षुण्ण रखने और संगीत के विकास हेतु ग्वालियर रियासत के महाराज माधवराव सिंधिया (प्रथम) ने 1924 में उर्स तानसेन नाम से संगीत समारोह का विधिवत आरंभ किया था। इसका प्रारंभ हरिकथा से तथा तानसेन की समाधि पर चादर चढ़ाने से हुआ करता था। 1924 के पहले भी तानसेन की समाधि पर जाकर ग्वालियर के संगीतकार वर्ष में एक बार इकट्ठा हुआ करते थे और अपने गायन-वादन से संगीत सम्राट को श्रद्धांजलि दिया करते थे। अतः यह आयोजन बहुत पुराना है।

प्रारंभिक वर्षों में आवागमन की सुविधा अच्छी नहीं थी, अतः कलाकार अपने साजोसामान लेकर पैदल तानसेन समारोह तक पहुंचते थे। कलाकार स्वतः प्रेरणा से तानसेन की समाधि पर शीश नवाते, मस्ती में गाते और जनता का मन मोहते थे। बताते हैं कि एक बार तानसेन की समाधि पर प्रस्तुति देने ग्वालियर घराने के उस्ताद गायक हद्दू खाँ साहब बैलगाड़ी से जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी का एक बैल गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। हद्दू खाँ साहब दुखी हो गए कि अब वह नहीं पहुंच पाएंगे। साथ में उनका एक शागिर्द भी था, उसने कहा- उस्ताद जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, जब आपके सामने बैल खड़ा है। यह कहकर शागिर्द ने बैलगाड़ी का पाया अपने कंधे पर रखा और उस्ताद को आयोजन स्थल तक पहुंचाया। उस समय संगीत की गुरु-शिष्य परंपरा ग्वालियर में चरम पर थी।

मैं चार वर्ष की आयु से यानी वर्ष 1938 से ही पिताजी पंडित कृष्णराव के साथ इस आयोजन में जाता था। पिताजी गायन की प्रस्तुति देते थे। स्वाधीनता और देशी रियासतों के समाप्त होने के पश्चात तय किया गया कि इस समारोह को राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक कड़ी के रूप में मनाया जाए। मध्य प्रदेश शासन तथा आकाशवाणी ने मिलकर इसकी पहल की। आकाशवाणी से इसका प्रत्यक्ष प्रसारण किया गया। समारोह के आयोजन की जिम्मेदारी कालांतर में राज्य शासन ने ले ली। अब यह जिम्मेदारी उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी पर है।

जब रेडियो से समारोह का सजीव प्रसारण होने लगा, तब कलाकार का प्रस्तुति का समय निर्धारित कर दिया गया। लाल और हरी बत्ती का इंतजाम किया गया। समय समाप्त होने पर लाल बत्ती जलाई जाती। एक बार पंडित जसराज प्रस्तुति दे रहे थे। जब उनका समय समाप्त हुआ तो लाल बत्ती जलाई गई, लेकिन पंडित जी ने नजरअंदाज कर दिया। जब बार-बार लाल बत्ती जलने लगी, तो पंडित जी ने लाल बत्ती का बल्ब निकालकर अपनी जेब में डाल लिया और गाते रहे।

ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर दूर बेहट ग्राम तानसेन की जन्मस्थली है। इस समारोह के अनुक्रम में वहां भी कार्यक्रम किया जाता है। ग्रामीण जनता यहां बिभोर होकर संगीत सुनती है। अब नवोदित कलाकारों को भी अवसर दिया जाता है। यह मंच कलाकारों को यशस्वी बनता है।

(लेखक ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि गायक हैं।)

भारतीय परिधान को मिल रही पहचान | **बढ़ती लोकप्रियता** | पारंपरिकता और आधुनिकता के मेल से हो रहा नव प्रयोग

वैश्विक स्तर पर साड़ी को नया रूप दे रहे हैं जेन जी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

भारतीय साड़ी को अब वैश्विक परिधान के रूप में पहचान मिल रही है। जेन जी डिजाइनर परंपरा और आधुनिक वैश्विक परिधान कला के मेल से भारतीय साड़ी को नया आकर्षक रूप दे रहे हैं, जिसमें पारंपरिक ड्रेप से लेकर आधुनिक बोहो-चिक 'फैशन' तक का इस्तेमाल हो रहा है। आधुनिक 'स्टायलिश' साड़ी अब भारत से लेकर ब्रिटेन समेत यूरोप के विभिन्न हिस्से में कारपोरेट बोर्ड कक्ष से लेकर पार्टी तक लोगों की पसंद बन रही है। चाहे फिश कट लहंगा साड़ी हो या काश्ता साड़ी या अन्य, साड़ी आकर्षक परिधान बन रही है।

एक महीने पहले लंदनवासियों के बीच काश्ता साड़ी एक बोहो चिक प्रतीक बन गई। आधुनिक बोहो-चिक फैशन, बोहेमियन (बोहो) और हिप्पी शैलियों को समकालीन, परिष्कृत तत्वों के साथ मिलाकर एक मुक्त-भावना और आरामदायक लेकिन स्टाइलिश लुक देता है, जिसमें ढीले-ढाले कपड़े शामिल होते हैं, जो आराम, रचनात्मकता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मिश्रण है। आधुनिक बोहो-चिक शैली स्वतंत्रता, रचनात्मकता और सहजता को दर्शाती है, जो हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है और इसे आसानी से व्यक्तिगत स्पर्श के साथ अपनाया जा सकता है। परिधान विशेषज्ञ अश्विनी नारायण कहती हैं, 'किसने सोचा होगा कि महाराष्ट्र की ग्रामीण महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली धोती जैसी यह साड़ी फैशन में इतनी लोकप्रिय हो जाएगी?' काश्ता साड़ी अब समारोह में जाने वालों का पसंदीदा पहनावा बन गई है। अमीर से लेकर आम आदमी तक सबकी पसंद साड़ी है। जेन जी डिजाइनर इसे आकर्षक रूप-आकार दे रहे हैं।

कोविड के बाद, जेन जी की नई पीढ़ी ने साड़ी को अपने तरीके से अपनाया है, इसे नए सिरे से गढ़ा है और ब्रांडेड लेबल के दबदबे, कुर्ता-जींस की सर्वव्यापकता या सलवार-कुर्ता की एकरूपता को तोड़ते हुए इसे नया रूप दिया है। चाहे वह 'प्री-प्लीटेड' साड़ियां हों, 'बेल्ट' के साथ 'ट्राइबल ड्रेप्स' हों, 'सैश स्टाइल गाउन' हों या 'हाई-हेम्ड, हरेम पैंट ट्विस्ट' हों, युवा महिलाएं अब साड़ी को दैनिक यात्रा, 'काफी डेट', 'बोर्डरूम प्रेजेंटेशन' और शाम के काकटेल के लिए उपयुक्त रूप से आरामदायक परिधान के रूप में फिर से खोज रहे हैं।

जेन जी डिजाइनरों ने इसे लचीला बना दिया है, इसकी औपचारिकता को रोजमर्रा की जिंदगी से और इसके व्याकरण को सहजता से तोड़ दिया है। साड़ी अतीत में वापस जाने और उससे ऊर्जा प्राप्त करने का एक माध्यम है। हम एक बेहतर दुनिया में भावनात्मक सहारा तलाश रहे हैं। उदारीकरण के बाद, 2000 के दशक की शुरुआत में, वैश्विक ब्रांडों के प्रति दीवानगी और चीनी रेशम की भरमार ने उन्हें अपने देश के रेशम और उसके साथ-साथ अपनी वस्त्र विरासत की खोज करने के लिए प्रेरित किया।

साड़ी इतिहासकार ऋता कपूर चिश्ती की पुस्तकों ने साड़ी को समझने में मदद की है। भारत में करीब 31 तरह की साड़ी शैली हैं, इनको अब पश्चिमी परिधान कला के मेल से विश्व स्तर पर पेश किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय डिजाइन वैश्विक बन रहे हैं। विश्व में साड़ी खुद को उपनिवेशवाद से मुक्त करने की प्रतीक बन गई है।

भारतीय दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर नस्लवादी हमलों से अछूते नहीं हैं। साड़ी इतनी सहज है कि इसमें कुछ भी बेमेल नहीं लगता है। चिश्ती का मानना है कि साड़ियों में नए सिरे से जागी रुचि ने क्षेत्रीय बुनाई को संरक्षित करने की संभावनाएं खोल दी हैं। जेन जी ने तरुण ताहिलियानी, रितु कुमार, मसाबा गुप्ता, आर्ची चोपड़ा, गाया बाय आर्ची और अमित अग्रवाल जैसे डिजाइनरों को भी विविधता लाने के लिए प्रेरित किया है।

Jansatta Page No-3

आस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर हमला

यहूदी समुदाय के उत्सव में दो आतंकियों ने गोलियां चलाईं; 11 की मौत, 29 घायल

सिडनी के बोंडी बीच पर रविवार को हुए आतंकी हमले के बाद पुलिस।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

आस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर रविवार को यहूदी समुदाय के उत्सव के दौरान दो बंदूकधारियों की अंधाधुंध गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई। आस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया जबकि एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया।

सिडनी के न्यू साउथ वेल्स पुलिस आयुक्त एम लेनयान ने बताया कि इस हमले में दो पुलिस अधिकारियों समेत 29 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। राज्य प्रमुख क्रिस मिन्स ने कहा, 'इस हमले का निशाना सिडनी का यहूदी समुदाय था।'

यहूदी त्योहार हनुक्का की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों लोग बोंडी बीच पर 'चानुका बाय द सी' नामक कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए थे। आस्ट्रेलियाई टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित फुटेज में देखा जा सकता है कि कोई व्यक्ति बंदूकधारियों में से एक को पकड़कर उससे हथियार छीन लेता है और फिर वही हथियार उस पर तान देता है। मेलबर्न निवासी 32 वर्षीय लाचलान मोरान ने बताया कि वह पास ही में अपने परिवार का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी।

उन्होंने कहा, 'सब लोग अपना सारा सामान छोड़कर भागने लगे, लोग रो रहे थे, और यह सब बहुत भयानक था।' लिस ने कहा कि उसका अभियान जारी है और 'आसपास के इलाके में मिली कई संदिग्ध वस्तुओं' की जांच विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जिसमें एक संदिग्ध की कार में बरामद किया गया आईईडी भी शामिल है। 9

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि उनकी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा, 'बोंडी बीच के दृश्य चौंकाने वाले और दुखद हैं। पुलिस और आपातकालीन कर्मी मौके पर मौजूद हैं और लोगों की जान बचाने के लिए प्रयासरत हैं।'

Jansatta Page No-3

आस्ट्रेलिया में यहूदियों पर आतंकी हमला, 12 की मौत

- सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का त्योहार मना रहे सैकड़ों यहूदियों पर दो हमलावरों ने बरसाईं गोलियां
- हमलावरों में एक पाकिस्तानी मूल का, पुलिस ने एक मारा गिराया और दूसरे को किया गिरफ्तार
- पीएम मोदी समेत दुनियाभर के नेताओं ने की आतंकी हमले की निंदा, पीड़ितों के प्रति जताई संवेदना

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

आस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बोंडी बीच पर हनुक्का त्योहार मनाने के लिए एकत्रित हुए यहूदियों पर रविवार शाम दो हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस हमले में 12 लोग मारे गए और 29 अन्य घायल हैं। मरने वालों में एक इजरायली नागरिक शामिल है, जबकि घायलों में एक बच्चा और दो पुलिस अधिकारी भी हैं। आस्ट्रेलिया पुलिस ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी हालत गंभीर है। एक हमलावर की पहचान पाकिस्तानी मूल के 24 वर्षीय नवीद अकरम के रूप में हुई है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की।

दुनियाभर के नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमले की निंदा करते हुए प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' रखता है और इसके सभी रूपों व अभिव्यक्तियों के विरुद्ध लड़ाई का समर्थन करता है।

सिडनी में बोंडी बीच पर अंधाधुंध गोलीबारी करते काले कपड़े पहने दो हमलावर। इसके बाद जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते लोग। एएफपी

यह यहूदी-विरोधी और आतंकी कृत्य, जिसने आस्ट्रेलिया के दिल पर हमला किया : अल्बनीज

आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कैनबरा में पत्रकारों से कहा कि वह इस नरसंहार से बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा, यह हनुक्का के पहले दिन यहूदी आस्ट्रेलियाई लोगों को निशाना बनाकर किया गया हमला है। यह यहूदी-विरोधी और आतंकी कृत्य है जिसने आस्ट्रेलिया के दिल पर हमला किया है। उन्होंने कहा, 'मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम हिंसा और नफरत के इस घिनौने कृत्य को खत्म करेंगे। यह राष्ट्रीय एकता का क्षण है, जिसमें सभी आस्ट्रेलियाई अपने यहूदी आस्ट्रेलियाई लोगों को गले लगाएंगे।'

एपी के अनुसार, सिडनी आस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित है। राज्य के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने कहा कि यह हमला सिडनी के यहूदी समुदाय को निशाना बनाने के लिए ही किया गया। उन्होंने कहा, 'आस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय के लिए आज रात हमारा दिल द्रवित है। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि इस प्राचीन त्योहार को मनाते समय अपने प्रियजनों को मरते देखकर उन्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी।'

सिडनी में छात्र था पाकिस्तानी हमलावर नवीद अकरम

इंटरनेट पर प्रसारित पाकिस्तानी मूल के हमलावर नवीद और उसका ड्राइविंग लाइसेंस।

आस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, नवीद अकरम मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। वह सिडनी के अल-मुराद इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। आनलाइन प्रसारित हो रही एक लाइसेंस फोटो में उसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी पहने देखा जा सकता है।

बोंडी बीच के आसपास रहती है एक तिहाई यहूदी आबादी : आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आस्ट्रेलिया की 2.8 करोड़ की आबादी में लगभग 1.17 लाख यहूदी हैं। इनमें एक तिहाई यहूदी सिडनी के इसी बोंडी बीच के आसपास रहती है

पुलिस कमिश्नर एम. लैन्योन के अनुसार, बोंडी बीच पर एक हजार से अधिक लोग हनुक्का यहूदी त्योहार की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। स्थानीय समयानुसार लगभग 6.30 बजे दो हमलावरों ने लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाके में मिली कई संदिग्ध वस्तुओं की जांच की जा रही है, इनमें आइईडी भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी रायटर ने लैन्योन के हवाले से बताया कि पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि हमले में कोई तीसरा हमलावर भी शामिल था अथवा नहीं। साथ ही बम निरोधक दस्ते आइईडी पर काम कर रहे हैं। चबाड ने मृतकों में से एक की पहचान रब्बी एली श्लैंगर के रूप में की है जो चबाड आफ बोंडी में असिस्टेंट रब्बी थे और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों में से एक थे। चबाड एक आर्थोडाक्स यहूदी मूवमेंट है। यह दुनियाभर में कई सेंटर चलाता है जो यहूदी यात्रियों के बीच लोकप्रिय हैं और अक्सर प्रमुख यहूदी त्योहारों के दौरान बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है।

आस्ट्रेलिया के पीएम को दी थी चेतावनी : नेतन्याहू पेज>>11

Dainik Jagaran Page No-1

दावोस की तैयारी : भारत से जाएंगे सौ से अधिक सीईओ

विश्व आर्थिक मंच की बैठक में चार मुख्यमंत्री होंगे शामिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

अगले महीने होने वाली विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू सहित भारत के चार मुख्यमंत्री और 100 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शामिल होंगे। यह पांच दिवसीय वार्षिक बैठक 19 से 23 जनवरी, 2026 तक चलेगी और इसमें करीब 130 देशों से लगभग 3,000 वैश्विक नेता शामिल होंगे। इनमें करीब 60 राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है।

महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी और मध्य प्रदेश के मोहन यादव भी दावोस पहुंचेंगे। इन चार राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों की भी डब्ल्यूईएफ वार्षिक बैठक 2026 में मजबूत मौजूदगी रहने की उम्मीद है। यह बैठक 'संवाद की भावना' विषय के तहत आयोजित की जाएगी। बैठक में भाग लेने वाले केंद्रीय मंत्रियों के नामों की घोषणा जल्द किए जाने की संभावना है।

> 19 से 23 जनवरी 2026 तक चलेगी और इसमें करीब 130 देशों से लगभग 3,000 वैश्विक नेता शामिल होंगे। इनमें करीब 60 राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे।

दुनिया भर के प्रभावशाली उद्योगपतियों और कारोबारी नेताओं की इस बैठक में भारत से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी, टाटा समूह के एन चंद्रशेखरन, बजाज समूह के संजीव बजाज और जुबिलेंट भरतिया समूह के हरि एस भरतिया के शामिल होने की उम्मीद है। दावोस जाने वाले अन्य भारतीय कारपोरेट नेताओं में एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह के नादिर गोदरेज, जेएसडब्ल्यू समूह के सज्जन जिंदल, जेरोधा के निखिल, भारती समूह के सुनील भारती, इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि, इन्फोसिस के सीईओ सलिल एस पारेख, विप्रो के ऋषद प्रेमजी, एस्सार के सीईओ प्रशांत रुइया और पेटीएम के विजय शेखर शर्मा हैं।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के अलावा कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख भी दावोस जाएंगे, जिनमें गेल के संदीप कुमार गुप्ता, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन सी एस सेट्टी, एनटीपीसी के गुरदीप सिंह और आरईसी के जितेंद्र श्रीवास्तव शामिल हैं। जी-7, जी-20, ब्रिक्स देशों सहित अन्य देशों के नेता और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी इस बैठक में भाग लेंगे।

Jansatta Page No-10

रोचक | उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार की नई योजना

उत्तराखंड सरकार जल्द शुरू करेगी 'हिम तेंदुआ' पर्यटन

देहरादून, 14 दिसंबर (भाषा)।

उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार लद्दाख माडल पर जल्द 'स्नो लेपर्ड टूर' (हिम तेंदुआ टूर) शुरू करने जा रही है। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार देर रात हुई राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों की एक बैठक के दौरान प्रदेश के पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने यह जानकारी दी।

गर्ब्याल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू किए जा रहे इस टूर के तहत शीतकाल में गंगोत्री जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों को नियंत्रित रूप से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रायोगिक तौर पर हिम तेंदुआ पर्यटन संचालित किया जाएगा। पर्यटन सचिव ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित करना है। अधिकारी के मुताबिक, 'स्नो लेपर्ड टूर' से 'होमस्टे', स्थानीय गाइड, साहसिक पर्यटन एवं अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन के लिए शीतकालीन चारधाम यात्रा, साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक उत्सव एवं वन्यजीव पर्यटन से संबंधित एक व्यापक कार्ययोजना लागू की जा रही है। गर्ब्याल ने कहा कि कार्ययोजना के तहत औली, खलिया टाप, बेदनीधार आदि विभिन्न क्षेत्रों में स्कीइंग, ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग एवं रैपलिंग जैसे साहसिक आयोजन किए जाएंगे जबकि मसूरी, नैनीताल एवं उत्तरकाशी में विंटर कार्निवल, ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव तथा जिम कॉर्बेट, नंधौर एवं गंगोत्री क्षेत्र में वन्यजीव पर्यटन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को वर्षभर पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है ।

पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू किए जा रहे इस टूर के तहत शीतकाल में गंगोत्री जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों को नियंत्रित रूप से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रायोगिक तौर पर हिम तेंदुआ पर्यटन संचालित किया जाएगा।

Jansatta Page No-10

नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन : जेलेंस्की

वाट्सएप समूह में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, रूस को क्षेत्र सौंपने के लिए अमेरिका दबाव न बनाए

बर्लिन, 14 दिसंबर (एपी)।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटी मिलने पर नाटो में शामिल नहीं होने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका उन पर रूस को क्षेत्र सौंपने के लिए दबाव न बनाए। जेलेंस्की युद्ध समाप्ति पर अमेरिका के राजनयिकों के साथ बातचीत के लिए बर्लिन पहुंचे थे।

जेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि ये सुरक्षा गारंटी रूस को एक बार फिर से युद्ध छेड़ने से रोकने का अवसर हैं और यह हमारी ओर से एक समझौता है। कोई भी सुरक्षा आश्वासन कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिए और अमेरिकी कांग्रेस द्वारा समर्थित होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्टटगार्ट में यूक्रेनी और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद उन्हें अपनी टीम से जानकारी मिलने की उम्मीद है।

जेलेंस्की, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकाफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ होने वाली अपेक्षित वार्ता से पहले चांसलरी पहुंचे। बर्लिन में हुई यह वार्ता यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों के बीच होने वाली सिलसिलेवार बैठकों का हिस्सा है। जेलेंस्की ने वार्ता से पहले 'वाट्सएप समूह चैट' पर आडियो क्लिप में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों ने नाटो में शामिल होने के यूक्रेन के प्रयास को खारिज किया है इसलिए कीव को उम्मीद है कि पश्चिम उसे नाटो सदस्यों को दी गई गारंटी के समान ही गारंटी प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा, ये सुरक्षा गारंटी रूस को एक बार फिर से युद्ध छेड़ने से रोकने का अवसर हैं। और यह हमारी ओर से एक समझौता है। जेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी सुरक्षा आश्वासन कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिए और अमेरिकी कांग्रेस द्वारा समर्थित होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्टटगार्ट में यूक्रेनी और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद उन्हें अपनी टीम से जानकारी मिलने की उम्मीद है।

ट्रंप, रूस से युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए कह रहे हैं और समझौते पर सहमति बनने में हो रही देरी से लगातार परेशान हो रहे हैं। संभावित समझौतों पर सहमति बनाने में कई बड़ी बाधाएं आई हैं, जिनमें यूक्रेन के पूर्वी दोनेत्सक क्षेत्र पर नियंत्रण भी शामिल है, जिस पर ज्यादातर रूसी सेनाओं का कब्जा है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से दोनेत्स्क क्षेत्र के उस हिस्से से अपनी सेना वापस बुलाने की मांग की, जो अब भी यूक्रेनी सैनिकों के नियंत्रण में है। हालांकि, कीव ने इस मांग को खारिज किया है। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए दोनेत्सक से पीछे हटने और वहां एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र बनाने का विचार रखा था, जिसे उन्होंने अव्यवहारिक बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इसे उचित नहीं मानता, क्योंकि इस आर्थिक क्षेत्र का प्रबंधन कौन करेगा? जेलेंस्की ने कहा, अगर हम किसी सीमा रेखा के साथ किसी बफर जोन की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं और हमारा मानना है कि वहां केवल पुलिस बल होना चाहिए तथा सैनिकों को वापस बुला लिया जाना चाहिए, तो सवाल बहुत सीधा है।

Jansatta Page No-11

विश्लेषण दक्षिण एशियाई क्षेत्र को लेकर नेपाल की राजधानी काठमांडो में विशेषज्ञों और अधिकारियों ने कहा

पर्यावरणीय परिवर्तन अर्थशास्त्र को समझना महत्त्वपूर्ण

काठमांडो, 14 दिसंबर (भाषा)।

नेपाल की राजधानी काठमांडो में विशेषज्ञों और अधिकारियों के अनुसार तेज आर्थिक विकास के दौर से गुजर रहे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय परिवर्तन और विकास के अर्थशास्त्र को समझना महत्त्वपूर्ण है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिसमें हिंदू कुश हिमालयी देश आते हैं। इन्हें जलवायु और पर्यावरण के लिहाज से दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों ने जैव विविधता वित्त, वन बहाली, जलवायु अनुकूलन और कृषि सहित टिकाऊ आजीविका पर केंद्रित एक सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा की। नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) के गवर्नर बिस्वनाथ पौडेल ने चेतावनी दी कि केवल बैंक ऋण देने से कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान नहीं हो सकता है और उन्होंने ऋण रोकने के लिए राजस्व स्थिरता एवं मूल्य निश्चितता की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि ऋण किसानों पर बोझ बन जाता है। गवर्नर पौडेल ने 'नेपाल में कृषि क्षेत्र में बैंक ऋणः मुद्दे और अवसर' विषय पर अपने मुख्य भाषण में कहा, वित्तपोषण एकमात्र समाधान नहीं है। कृषि में राजस्व स्थिरता ही वास्तविक समाधान है। पौडेल ने बदलती जलवायु का सामना कर रहे किसानों के कल्याण के लिए कृषि बीमा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा, कीमतों में स्थिरता के बिना ऋण सहायता के बजाय बोझ बन जाता है। पौडेल ने काठमांडू में 'विकास, पर्यावरण और पर्वत' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में ये बातें कहीं।

एनआरबी के गवर्नर बिस्वनाथ पौडेल ने चेतावनी दी कि केवल बैंक ऋण देने से कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान नहीं हो सकता है और उन्होंने ऋण रोकने के लिए राजस्व स्थिरता एवं मूल्य निश्चितता की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि ऋण किसानों पर बोझ बन जाता है।

पौडेल ने बदलती जलवायु का सामना कर रहे किसानों के कल्याण के लिए कृषि बीमा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा, कीमतों में स्थिरता के बिना ऋण सहायता के बजाय बोझ बन जाता है। पौडेल ने काठमांडू में 'विकास, पर्यावरण और पर्वत' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में ये बातें कहीं।

यह सम्मेलन दक्षिण एशियाई विकास एवं पर्यावरण अर्थशास्त्र नेटवर्क (एसएएनडीईई) की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन इंटरनेशनल सेंटर फार इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आइसीआइएमओडी) ने किया था जो आठ हिमालयी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। आइसीआइएमओडी के महानिदेशक पेमा ग्यामत्शो ने कहा कि एसएएनडीईई ने दक्षिण एशिया में गरीबी, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के अंतर्संबंध को समझने तथा उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से आगे बढ़ाया है।

Jansatta Page No-11

भारत ने पहली बार स्क्वाश विश्व कप का खिताब जीता

चेन्नई, 14 दिसंबर (भाषा)।

भारत ने स्क्वाश विश्व कप के फाइनल में रविवार को हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली बार इस खिताब को जीत इतिहास रच दिया। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2023 में कांस्य पदक जीतना था। यह खिताबी जीत भारतीय स्क्वाश के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर है क्योंकि यह खेल लास एंजिल्स 2028 में ओलंपिक में अपना पदार्पण करने जा रहा है। मिश्रित टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त भारत ने बिना कोई मैच हारे खिताब अपने नाम किया। ग्रुप चरण में स्विट्जरलैंड और ब्राजील को समान 4-0 के अंतर से हराने के बाद भारत ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में क्रमश: दक्षिण अफ्रीका और दो बार के चैंपियन मिस्र को 3-0 से हराया।

दैनिक जागरण
सप्तरंग
साहित्य और संगीत का
सोमवार, 15 दिसंबर, 2025

भिखारी ठाकुर का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना बड़ा था कि सबने अपने-अपने दृष्टिकोण से उन्हें देखा। एकांगी विमर्श से भ्रम भी पैदा हुआ। जबकि सच यह है कि उन्हें किसी भी खांचे में बांधा नहीं जा सकता। उनकी रचनाधर्मिता भाषा और समय की सीमा में नहीं बंधी। भिखारी ठाकुर की जन्मजयंती (18 दिसंबर) पर एक विमर्श...

विमर्श

निराला बिदेसिया
पटना

किसी भी खांचे से परे भिखारी ठाकुर

भिखारी ठाकुर (18 दिसंबर, 1887 - 10 जुलाई, 1971) इलस्ट्रेशन : अवधेश राजपूत

बात करीब डेढ़ दशक पहले की है। पटना में हिंदी के कुछ बड़े आलोचकों और साहित्यकारों का जमावड़ा था। बात भिखारी ठाकुर पर चल पड़ी। अपने तर्क गढ़ते हुए भिखारी ठाकुर को नास्तिक और जातीय प्रताड़ना झेले एक पीड़ित कलाकार के फ्रेम में बांधने की कोशिशें हुईं। पिछले दो-तीन दशकों से, जबसे भिखारी ठाकुर पर बात करने का सिलसिला बढ़ा है, सबने अपने-अपने भिखारी ठाकुर गढ़ने की कोशिशें की हैं। भिखारी को लेकर भ्रम का भंवरजाल बढ़ाया गया है। कुछ सिर्फ जातीय खांचे में भिखारी को कैद कर अपने नाम को उनके खोजकर्ता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ उन्हें नास्तिक के रूप में स्थापित करने के प्रयास में हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो यह भ्रम फैलाते हैं कि उन्होंने भिखारी ठाकुर पर काम किया, तब उन्हें कोई जान सका, वरना वे विस्मृति के गर्त में समा चुके होते।

जगजाहिर है कि भिखारी ठाकुर वंचित समुदाय से थे। बिहार के कठिन भौगोलिक स्थितियों वाले गंगा के दियारा में उनका गांव था, कुतुबपुर दियरा। भिखारी ठाकुर पर काम उनके रहते ही होना शुरू हो गया था। अपने समय में ही उनका स्टारडम बड़ा हो चुका था। जिस दौर में भिखारी ठाकुर बिहार में सक्रिय थे, उस समय एक और ठाकुर बिहार की राजनीति में जननायक के रूप में उभरे, वह थे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। कहते हैं कि उस समय जन-जन के बीच भिखारी ठाकुर का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर से अधिक चर्चित था। भिखारी ठाकुर ने मुंबई सिनेमा में काम किया। आकाशवाणी गए। काशी नरेश उन्हें अपने यहां बुलाते रहे।

उनके नास्तिक होने के भ्रम से निकलना चाहिए। जो भिखारी ठाकुर अपने हर नाटक के पहले गणेश वंदना करते थे, रामा हो रामा... उनके गीतों का प्रमुख टेक था, जो गंगा मैया को गोहराते थे, वह नास्तिक कैसे हो सकते थे और किस कोण से! वह भगवान राम की 67 पुश्तों से लेकर जनक की पुश्तों तक का बखान करते थे, भोजपुरी में राम को उनसे ज्यादा कौन साध सका उनके समय में?

भिखारी ठाकुर पर उनके रहते पहला ठोस काम किया महेश्वराचार्य ने। महेश्वराचार्य ने वर्ष 1935 से ही भिखारी पर लिखना शुरू किया। पहले उनके निबंधों का समीक्षात्मक संग्रह 'जनकवि भिखारी ठाकुर' नाम से आया, बाद में भिखारी की चुनिंदा रचनाओं का समीक्षात्मक संग्रह 'भिखारी' नाम से आया। महेश्वराचार्य तब की प्रसिद्ध पत्रिका 'सरस्वती' के सहायक संपादक थे। भिखारी के समय में ही जगदीश चंद्र माथुर ने उन पर बारीकी से नजर रखी और भिखारी की मृत्यु के बाद 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' में आलेख लिखा, जो बहुत चर्चित हुआ। भिखारी के समय में ही रांची के संत जेवियर कालेज के हिंदी के प्राध्यापक रामसुहाग सिंह ने कलकत्ता (अब कोलकाता) जाकर उनका इंटरव्यू किया। वह इकलौता इंटरव्यू है भिखारी ठाकुर का। भिखारी ठाकुर को समझने-जानने के लिए ये तीनों काम, प्रामाणिक स्रोत की तरह हैं।

एकतरफा विमर्श से निकलकर आज के समय में उनके काम का मूल्यांकन नए सिरे से किए जाने की आवश्यकता है। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के महान कलाकार हुए, पर अब वे उस दायरे से कब का निकल चुके हैं और हिंदी पट्टी के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अवलंब बन चुके हैं। कई रूप में- नाटककार के रूप में, गीतकार के रूप में, कवि के रूप में, भाषासेवी के रूप में, गायक के रूप में... सृजन के हर मोर्चे पर, लेकिन उससे ज्यादा एक और रूप में। पहचान की राजनीति व संकट के दौर में भिखारी का व्यक्तित्व और कृतित्व लाइट हाउस की तरह उभरता है। उनका पूरा जीवन यह बताता है कि पहचान बनाने के लिए बड़ी-बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती और न ही किसी बनी-बनाई राह पर चलना जरूरी होता है। उनका पूरा रचनाकर्म इस भ्रम को तोड़ता है कि जो मुख्यधारा है, उसमें शामिल हुए बिना न तो पहचान बन सकती है, ना ही जीवन गुजारा जा सकता है।

भिखारी करीब 30 वर्ष की आयु में दोबारा पढ़ाई-लिखाई से पहले उस्तरा चला रहे थे। यानी उस उम्र में उन्होंने अक्षरों की दुनिया से सरोकारी वास्ता बनाना शुरू किया, जिस आयु में कुछ नहीं करने पर किसी नौजवान के भविष्य का मर्सिया पढ़ दिया जाता है, उस आयु में भिखारी ठाकुर एक नई शुरुआत करते हैं। वह सिर्फ भोजपुरी जानते थे, अतः उसमें ही उन्होंने काम करना शुरू किया। जो किया, उसे आज संसार जानता है। अपने जीवन से वह संकेत देते हैं कि किसी भी काम को करने की, विशेषकर सृजन कर्म के लिए कोई निर्धारित आयु नहीं होती।

भिखारी जब कलाकार बनते हैं, तो घोर पेशेवर। अपने दल का गठन करते हैं। सबके भरण-पोषण का भी इंतजाम करते हैं। जहां जाते हैं, वहां से माला उठाने को कहते हैं यानी जो खाना-दाना देता, वहीं जाते थे। कला को शुल्करहित कभी नहीं रखते। एक गरिमा, एक मान-सम्मान चाहते थे खुद का, अपनी टीम का। जब वह वृद्ध हो जाते हैं, तब यह भी कहते हैं कि कलाकारों के लिए पेंशन का इंतजाम किया जाना चाहिए।

ऐसे अनेक पहलुओं को देखेंगे, तो भिखारी ठाकुर अपने समय के सवाल भी उठा रहे थे और समय के आगे के सवाल भी। उनके दो-तीन नाटक बहुत मशहूर है, 'बिदेसिया', 'बेटीबेचवा', 'गबरघिचोर' आदि। इन नाटकों में उनकी प्रगतिशीलता दिखती है। बिदेसिया में वह प्रेमिका को घर में स्वीकार्य करवाते हैं पत्नी रूप में। प्रेमिका भी कौन, एक रखैल। भिखारी के बिदेसिया नाटक का संदेश है कि जब किसी स्त्री के साथ संबंध बनाएं तो फिर उसे स्वीकार्य बनाएं। इसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े। इसी तरह 'गबरघिचोर' में वह स्त्री के तन और मन का मिलान कर स्त्री मन की स्वतंत्रता का सवाल उछालते हैं। इन सवालों को वे भोजपुरी समाज के बीच उठाते हैं, बताते हैं। जिस समय भिखारी ठाकुर यह सब ग्रामीण जनता के बीच दिखाते होंगे, उस समय के परिवेश की कल्पना की जा सकती है। पुरुषवादी वर्चस्व वाले समाज में इन सवालों को उठाना कितना कठिन रहा होगा, पर वह अपनी रचनाओं का 70 प्रतिशत हिस्सा स्त्रियों को समर्पित करते हैं।

वे सामाजिक-राजनीतिक हस्तक्षेप भी करते हैं, पर अपने तरीके से। गांव के बिंबों का इस्तेमाल कर वह विमर्श खड़ा करते थे। वह गमछा को बिंब बनाकर बात कहते हैं। तब गांव में लोग कुर्ता निकालकर खाना खाते थे, जबकि धोती और गमछा पहने रहते थे। कुर्ता-धोती और गमछा के बहाने भिखारी ने लिखा :

गूह-मूत के रास्ता तोपल से धोती वा मन वा चोपल,
नेटा-थूक रहत लपटाइल, तबहूं गमछी सूध कहाइल,
सूत के कुरता सूत के धोती, सूत से सूत सियाई होती,
चारु जना के एके जात, भात खात कुरता सरमात,
तवने सूत जनेव कहावत, जात से पदवी बड़का पावत,
कहत भिखारी सहजे बात, हमरा नइखे इहे बुझात।

इन पंक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप है, जिसे सामाजिक न्याय भी कहते हैं। ऐसे ही गहरे मर्म के साथ भिखारी ठाकुर आजीवन काम करते रहे। राजनीति से आगे संस्कृति को रखकर। संस्कृति को राजनीति का पथप्रदर्शक बनाकर।

niralabidesia@gmail.com

यूरोप में प्रवासियों के खिलाफ राजनीति तेज, नीतियों में भी बढ़ी सख्ती

लंदन, एपी: जिस यूरोप में कभी सहानुभूति व उदार भावना के साथ शरणार्थियों और प्रवासियों का स्वागत किया जाता था, अब उन्होंने ही इनके लिए दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए हैं। साथ ही प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने के लिए नीतियों में सख्ती भी की जा रही है। ब्रिटेन सहित कई देशों में हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर प्रवासी-विरोधी प्रदर्शन हुए हैं, जहां "उन्हें वापस भेजो" जैसे नारे लगाए गए। यह रुझान दक्षिणपंथी दलों के उभार और प्रवासन को लेकर बढ़ती राजनीतिक चिंता का परिणाम है।

ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में वे राजनीतिक दल जनमत सर्वेक्षणों में आगे चल रहे हैं, जो सामूहिक प्रवासन व निर्वासन को राष्ट्रीय पहचान के लिए खतरा बताते हैं। ब्रिटेन की रिफार्म यूके, जर्मनी की अल्टरनेटिव फार जर्मनी व फ्रांस की राष्ट्रव्यापी रैलियां इस प्रवृत्ति के प्रमुख उदाहरण हैं।

अमेरिकी राह पर यूरोप में बढ़ा विरोध:

- दक्षिणपंथ के उभार के साथ मुख्यधारा वाले दलों की भाषा भी बदली
- ब्रिटेन से फ्रांस तक प्रवासियों के खिलाफ उग्र बयानबाजी और प्रदर्शन तेज
- मानवाधिकार संगठनों ने चेताया- कट्टर रुख से सामाजिक विभाजन गहराएगा
- यूरोप में नस्लभेद के भी मामलों में भी हुआ इजाफा, अश्वेतों को खुलेआम दी जा रही हैं धमकियां

यूरोपीय देशों में प्रवासी पृष्ठभूमि वाले समुदायों के लिए मुश्किल बढ़ी है। प्रतीकात्मक

ब्रिटेन में बढ़े घृणा अपराध के मामले

ब्रिटेन में पुलिस आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 तक के एक वर्ष में 1.15 लाख से अधिक घृणा अपराध दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में दो प्रतिशत अधिक है। जुलाई 2024 में तीन बच्चियों की हत्या के बाद फैली अफवाहों ने भी हिंसक प्रवासी-विरोधी प्रदर्शनों को जन्म दिया। किंग्स कालेज लंदन की पालिसी यूनिट के डायरेक्टर बाबी डकी ने कहा कि ब्रिटेन में प्रवासियों के खिलाफ लोगों को राजनीतिक चरमपंथ की ओर धकेल रहा है।

शरणार्थियों के लिए बढ़ाई मुश्किलें

मुख्यधारा के राजनीतिक दल भी अब शरणार्थियों को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की सरकार और डेनमार्क जैसे देशों ने स्थायी निवास को कठिन बनाने और निर्वासन को आसान करने की नीतियां अपनाई हैं। विभिन्न मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि दक्षिणपंथ को संतुष्ट करने की कोशिशें और अधिक कट्टर मांगों का रास्ता खोलती हैं। विशेषज्ञों ने चेताया है कि जिम्मेदार राजनीतिक भाषा और संतुलित नीतियों के बिना यह बढ़ती विभाजनकारी राजनीति यूरोप के सामाजिक ताने-बाने को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।

विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त प्रवासी-विरोधी भाषा व नीतियों ने भी यूरोप में इस तरह की भावनाओं को बल दिया है। ट्रंप प्रशासन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में यूरोपीय देशों को प्रवासन के कारण आर्थिक गिरावट और सभ्यतागत क्षरण से जूझता बताया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं सोमालियाई प्रवासियों को अमेरिका में 'कचरा' बता दिया था।

यूरोप में पिछले एक दशक में प्रवासन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका एक कारण अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूक्रेन के संघर्षों से आए शरणार्थी हैं। हालांकि शरणार्थी कुल प्रवासन का छोटा हिस्सा हैं, फिर भी आर्थिक ठहराव, सोशल मीडिया पर ध्रुवीकरण और करिश्माई राष्ट्रवादी नेताओं के उभार ने प्रवासी-विरोधी भावनाओं को हवा दी है।

Dainik Jagaran Page No-11

तैयारी | **भारतीय नौसेना की शक्ति में होगा कई गुना इजाफा, इन्हें विश्व के सबसे उन्नत नौसैनिक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है**

एमएच-60आर हेलीकॉप्टर की दूसरी स्क्वाड्रन मिलेगी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय नौसेना के बेड़े में अत्याधुनिक एमएच-60आर मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर की एक नई स्क्वाड्रन शामिल होने जा रही है। यह हेलीकॉप्टर पारंपरिक युद्ध खतरों से निपटने में सक्षम है। इसके अलावा, यह विशेष हेलीकॉप्टर अनेक समुद्री चुनौतियों से निपटने में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा।

आधुनिक क्षमताओं से लैस एमएच-60आर हेलीकॉप्टर को विश्व के सबसे उन्नत नौसैनिक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। इसमें लगे आधुनिक हथियार, उन्नत सेंसर और अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम इसे एक बहुउद्देश्यीय और अत्यंत सक्षम प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इस स्क्वाड्रन के साथ ही भारतीय नौसेना अपनी आधुनिकीकरण और परिचालन क्षमता में वृद्धि की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। नौसेना के मुताबिक दूसरी अत्याधुनिक एमएच-60आर मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, 'आईएनएएस 335', को 17 दिसंबर को बेड़े में शामिल किया जाएगा। आईएनएस हंसा, गोवा में औपचारिक रूप से इसकी कमीशनिंग की जाएगी।

17 दिसंबर को एमएच-60आर मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, 'आईएनएएस 335', बेड़े में शामिल किया जाएगा

समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को मिलेगी बढ़त

आईएनएएस 335 की कमीशनिंग के साथ ही भारतीय नौसेना की इंटीग्रल एविएशन क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त होगी। यह स्क्वाड्रन समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता में अहम भूमिका निभाएगी। आईएनएएस 335 का कमीशनिंग समारोह नौसेना के भविष्य-उन्मुख, तकनीक-सशक्त और युद्ध-तैयार बल बनने की यात्रा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।

अमेरिकी सरकार के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर

भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी सरकार के साथ 7,995 करोड़ रुपए मूल्य के दो 'लेटर्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस' पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह समझौता भारतीय नौसेना के एमएच-60आर मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर बेड़े को फॉलो-ऑन सपोर्ट और फॉलो-ऑन सप्लाई सपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु है। समझौते पर 28 नवंबर को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे।

Hindustan Page No-16

किशाऊ परियोजना का खर्च नहीं उठाएगा हिप्र

राज्य ब्यूरो, जागरण ● शिमला

- **दिल्ली में हुई अपर यमुना बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार ने रखा पक्ष**
- **कहा, परियोजना से लोगों के विस्थापन से होने वाला नुकसान उठाना पड़ेगा**
- **90% राशि केंद्र को देनी, 10% हिमाचल व उत्तराखंड को**

किशाऊ बांध एवं जलविद्युत परियोजना >>

हिमाचल प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को स्पष्ट किया है कि टौंस नदी पर बनने वाली किशाऊ बांध एवं जलविद्युत परियोजना के लिए किसी भी प्रकार का खर्च वहन नहीं करेगी। इस परियोजना का पूरा वित्तीय भार भारत सरकार उठाए। 13 दिसंबर को दिल्ली में गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित अपर यमुना बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार ने पक्ष रखा।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि सिरमौर जिले और उत्तराखंड में बनने वाली परियोजना से विस्थापन होगा, खेती योग्य भूमि जलमग्न होगी और सबसे अधिक प्रभाव लोगों के विस्थापन से होने वाले नुकसान पर पड़ेगा। इसलिए हिमाचल सरकार ने उत्तराखंड के साथ 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी 1536 करोड़ रुपये में से देने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 90 प्रतिशत के खर्च के साथ-साथ हिमाचल सरकार के खर्च को भी वहन करना चाहिए।

इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार और हिमाचल-उत्तराखंड को 90:10 के अनुपात में खर्च उठाना था। दोनों राज्यों को कुल 1536 करोड़ के खर्च को आधा-आधा उठाना था। वर्ष 2018 के मूल्य सूचकांक के आधार पर डीपीआर तैयार की गई है, लेकिन अभी तक औपचारिकताएं धरातल पर नहीं उतरी हैं। बैठक में भाग लेकर लौटे मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अध्ययन के बाद पाया है कि इस परियोजना से हिमाचल को कई प्रकार का नुकसान होगा और इसके बदले कोई अधिक लाभ नहीं होगा।

पौंग व भाखड़ा विस्थापितों की समस्या का समाधान करे केंद्र : बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से तीन बिंदुओं को प्रमुखता से रखा गया। पहला था कि बीबीएमबी का 2011 से पहले का बकाया एरियर दिलाया जाए। इसके अतिरिक्त करीब छह दशक से भाखड़ा व पौंग विस्थापितों का स्थायी समाधान नहीं किया गया है। केंद्र सरकार पहले इन विस्थापितों को बसाने का प्रबंध करे।

किशाऊ बांध परियोजना : किसाऊ बांध एवं जल विद्युत परियोजना टौंस नदी पर बनने वाली बहुउद्देशीय परियोजना है। यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बनेगा। प्रारंभिक अनुमानित लागत लगभग 11,500 करोड़ थी। बांध की ऊंचाई 236 मीटर और लंबाई 680 मीटर होगी। भंडारण क्षमता 1324 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। चार पावर प्लांट से 660 मेगावाट (4×165 मेगावाट) विद्युत उत्पादन होगा।

Dainik Jagaran Page No-4

तमिल संस्कृति के महान संरक्षक थे सम्राट पेरुंबिदुगु मुथरैय्यर द्वितीय

- **मोदी ने युवाओं से किया आग्रह- सम्राट मुथरैय्यर द्वितीय के बारे में पढ़ें**
- **उपराष्ट्रपति ने तमिल सम्राट के सम्मान में जारी किया डाक टिकट**

नई दिल्ली, एएनआइ : पीएम नरेन्द्र मोदी ने सम्राट पेरुंबिदुगु मुथरैय्यर द्वितीय (सुवरण मारन) के सम्मान में डाक टिकट पर जारी किए जाने पर खुशी जताई है। मोदी ने रविवार को एक्स पर कहा,मुझे खुशी है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। वह प्रभावशाली प्रशासक थे और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वह तमिल संस्कृति के महान संरक्षक थे। मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि उनके असाधारण जीवन के बारे में पढ़ें।

इससे पहले उपराष्ट्रपति ने सम्राट मुथरैय्यर द्वितीय के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने भारत सरकार द्वारा तमिल संस्कृति व भाषा को दिए जा रहे निरंतर समर्थन को सराहा। काशी तमिल संगमम जैसी पहल की प्रशंसा की और उन तमिल राजाओं, नेताओं व स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के प्रयासों की सराहना की,जिन्हें अतीत में उचित सम्मान नहीं मिला था। सीपी राधाकृष्णन ने कहा, मुथरैय्यर द्वितीय प्राचीन तमिलनाडु के

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा सम्राट पेरुंबिदुगु मुथरैय्यर द्वितीय के सम्मान में जारी किया गया डाक टिकट। एएनआइ

सबसे प्रतिष्ठित शासकों में से एक थे। वह मुथरैय्यर वंश से संबंधित थे, जिसने सातवीं से नौवीं सदी में तमिलनाडु में शासन किया। सम्राट ने चार दशक तक तिरुचिरापल्ली से शासन किया। उनके शासनकाल को प्रशासनिक स्थिरता, क्षेत्रीय विस्तार, सांस्कृतिक संरक्षण जैसी विशेषताओं के लिए जाना जाता है।

Dainik Jagaran Page No-3

बदलेगा जीडीपी-आइआइपी को मापने का तरीका

आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने की तैयारी, ई-कामर्स का मूल्य भी किया जाएगा शामिल

राजीव कुमार ● जागरण

- खुदरा महंगाई के आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 2024 किया जाएगा
- सीपीआइ की नई बास्केट में मोबाइल फोन को किया जा सकता है शामिल

नई दिल्ली : नए साल में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), आइआइपी (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक) से लेकर खुदरा महंगाई दर का आधार वर्ष बदलने जा रहा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के जीडीपी का आंकड़ा आगामी 27 फरवरी को जारी होगा, जो नए आधार वर्ष पर आधारित होगा। अभी जीडीपी और आइआइपी के आंकड़ों का आधार वर्ष 2011-12 है, जिसे बदलकर 2022-23 किया जा रहा है।

दूसरी तरफ खुदरा महंगाई सूचकांक या दर (सीपीआइ) जिसका आधार वर्ष अभी 2012 है, उसे बदलकर 2024 किया जा रहा है। सीपीआइ को काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है, क्योंकि आरबीआइ के रेपो रेट के बदलाव में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खुदरा महंगाई दर को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आरबीआइ की है।

पिछले 10 सालों में खपत के पैटर्न से लेकर उत्पादन और सेवा सृजन के तरीके में बड़े बदलाव को देखते हुए सरकार जीडीपी, आइआइपी व सीपीआइ के आधार वर्ष में बदलाव कर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों से लोगों की खपत के पैटर्न में बदलाव हुआ है। अनाज की खरीदारी कम हुई है तो प्रोसेस्ड फूड, फल और सब्जी की खरीदारी बढ़ी है।

मोबाइल फोन जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। इसलिए सीपीआइ के नए बास्केट में मोबाइल फोन को शामिल किया जा सकता है। अभी सीपीआइ बास्केट में 299 उत्पाद शामिल हैं जिसे बढ़ाकर 350 से अधिक किया जा सकता है। सीपीआइ के मापने में अनाज का वेटेज कम किया जा सकता है। अभी सीपीआइ को मापने में अनाज और संबंधित उत्पाद का वेटेज 12.35 प्रतिशत है। सीपीआइ में अभी 47 प्रतिशत वेटेज खाद्य वस्तुओं का है। इसे भी कम किया जा सकता है।

जीडीपी मापने के लिए जीएसटी नेटवर्क का भी किया जाएगा इस्तेमाल

जीडीपी से लेकर सीपीआइ के मापने के लिए एकत्र किए जाने वाले डाटा में नए माध्यम को शामिल किया जा रहा है। सीपीआइ के लिए अब ई-कामर्स के मूल्य को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि पिछले दस सालों में ई-कामर्स पर होने वाली खरीदारी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वैसे ही जीडीपी को मापने के लिए जीएसटी नेटवर्क, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) तो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जैसे माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा। जीएसटी डाटा से मैन्यूफैक्चरिंग व सेवा सेक्टर से जुड़ी विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों और उनकी सटीक जानकारी मिलेगी। एनपीसीआइ से डिजिटल भुगतान का सटीक आंकड़ा मिलेगा जिससे छोटे-छोटे वित्तीय खर्च को भी जीडीपी में शामिल किया जा सकेगा।

जीएसटी फाइलिंग जीडीपी डाटा के लिए बड़ा माध्यम बनेगा

जीडीपी को मापने में आइटी और डिजिटल कामर्स का वेटेज या भार बढ़ाया जाएगा तो कुछ पारंपरिक सेक्टर के वेटेज को कम किया जाएगा। जीएसटी फाइलिंग जीडीपी डाटा के लिए बड़ा माध्यम बनेगा। वहीं एक आदमी वाली कंपनी के डाटा को भी जीडीपी में शामिल किया जाएगा। जोमैटो, स्विगी से जुड़े गिग वर्कर्स के उत्पादन डाटा अभी जीडीपी में शामिल नहीं होते हैं। नए डाटा में इन जैसे गिग वर्कर्स के उत्पादन को भी जीडीपी में शामिल किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2015 में जीडीपी के आधार वर्ष में बदलाव किया गया था।

Dainik Jagaran Page No-10

मखाना बोर्ड की तर्ज पर पान विकास बोर्ड होगा : रामकृपाल

- मीठापुर में सम्मान समारोह का आयोजन
- पान की खेती को कृषि का दर्जा देने की मांग

पटना, कासं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पान कृषकों को अश्वस्त किया है कि उनकी हर मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और मखाना बोर्ड की तर्ज पर पान विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

मौका था बिहार विधानसभा में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बिहार प्रदेश आदर्श चौरसिया सभा की ओर से सम्मान समारोह के आयोजन का। मीठापुर स्थित श्रीराज ट्रस्ट सभागार में रविवार को समारोह का शुभारंभ कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किया। इस दौरान कृषि मंत्री रामकृपाल यादव से बिहार में पान बोर्ड के गठन सहित पान कृषकों के आमदनी बढ़ाने वाले योजनाओं को जमीन पर लागू करने की मांग की मांग पान समाज ने की। इस मौके पर बिहार प्रदेश आदर्श चौरसिया सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी ने पान की खेती को कृषि का दर्जा देने की मांग की। पान की खेती पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करती है। इसलिए जो भी उसकी क्षतिपूर्ति है, वह कृषि के रूप में दिया जाए। इस दौरान कृषि मंत्री राम कृपाल यादव और दीघा के विधायक संजीव चौरसिया को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व विधान पार्षद रामचंद्र भारती, अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया सभा दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इंजीनियर आरके प्रसाद सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया।

बिहार प्रदेश आदर्श चौरसिया सभा की ओर से रविवार को श्रीराज ट्रस्ट सभागार में सम्मान समारोह का शुभारंभ करते कृषि मंत्री राम कृपाल यादव व अन्य।

Hindustan Page No-4

Useful For Mains

पशु-पक्षियों के संकेत और मौसम का रंग

आज के तकनीकी संसाधनों के दौर में भी पशु-पक्षियों के व्यवहार से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन उनके व्यवहार, प्रवास, प्रजनन और शारीरिक विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं।

अमित बैजनाथ गर्ग

राजस्थान में जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग ने हाल ही में एक अध्ययन में यह साबित किया है कि पक्षियों के घोंसले बनाने के तरीके से लेकर जानवरों के व्यवहार तक से मौसम के संकेतों को समझा जा सकता है। यह शोध 'इंटरनेशनल जर्नल आफ एनवायरमेंटल साइंस' में प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि जानवरों के व्यवहार से अस्सी फीसद तक मौसम का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। यह अध्ययन सिद्ध करता है कि पुराने समय से चली आ रही यह पारंपरिक जानकारी जो ग्रामीणों की ओर से इस्तेमाल की जाती रही है, अब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुकी है। उदाहरण के लिए मोर का नृत्य या कूजन मानसून की शुरुआत का संकेत देता है। इसी तरह चींटियों का भोजन इकट्ठा करना सूखा पड़ने का संकेत है।

विश्वविद्यालय के इस शोध दल का कहना है कि प्रकृति के संकेत आज भी कारगर हैं। पशु-पक्षियों के व्यवहार से मौसम का पूर्वानुमान लग जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन में इन बातों और तथ्यों की पुष्टि हुई है। यानी इससे पुरानी प्रथाओं के वैज्ञानिक प्रमाण साबित हुए हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि पशु-पक्षियों का व्यवहार आज भी मौसम के संकेत बताने में पूरी तरह सक्षम है। यह भी दावा किया गया है कि पारंपरिक ज्ञान का आज भी कोई तोड़ नहीं है। इसके संकेत आज भी वैज्ञानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं। यह भी बताया गया कि कैसे पुराने समय में लोग पारिस्थितिकी तंत्र के सदस्यों के व्यवहार से मौसम की भविष्यवाणी करते थे। लोमड़ी, सियार और अन्य जानवरों का व्यवहार भी इस प्रणाली का हिस्सा था। उदाहरण के लिए लोमड़ी खेतों में चूहों की संख्या को नियंत्रित करती है, जो कृषि के लिए अच्छा संकेत है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में भील, मीणा और बंजारा समुदायों के लोग अब भी पशु-पक्षियों के संकेतों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए लाल चींटियां जब अपने अंडे इधर-उधर ले जाती हैं, तो यह बारिश के करीब आने का संकेत होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के इन जीवों की सूझबूझ को दर्शाता है, जो मौसम की सटीक जानकारी देते हैं।

राजस्थान में मारवाड़ के गांवों में भी मौसम के पूर्वानुमान के लिए आज भी प्रकृति के संकेतों का अनुसरण किया जाता है। जहां एक ओर विज्ञान ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का विकास किया है, वहीं दूसरी ओर ये पारंपरिक तरीके आज भी बड़े काम आते हैं। पशु-पक्षियों के व्यवहार में मौसम के महत्त्वपूर्ण संकेत छिपे होते हैं। यह पारंपरिक ज्ञान न केवल ग्रामीणों के लिए, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक अहम संदर्भ बन चुका है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। प्राचीन समय से चली आ रही ये पद्धतियां अब आधुनिक विज्ञान के माध्यम से और अधिक प्रमाणित हो रही हैं।

पक्षियों और अन्य जीवों के पारंपरिक संकेतों के कुछ अर्थ होते हैं। सांप का पेड़ों पर चढ़ना बारिश की संभावना का पूर्वानुमान है। इसी

तरह लोमड़ी की उपस्थिति खेतों में चूहों का नियंत्रण होने का संकेत देती है। मौसम के साथ जीवन से पक्षियों के संकेत भी जुड़े हुए हैं, जैसे चिड़िया अथवा गौरैया का घर में घोंसला बनाना खुशहाली और तरक्की का संकेत है। पक्षियों के मौसम के संकेत में उनकी उड़ान की

> पशु-पक्षियों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को हमारे पूर्वजों ने पूरा मान और सम्मान दिया है। मनुष्य लंबे समय से इनके व्यवहार को बदलते मौसमों के संकेतक के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। कई लोक कथाएं और किस्से हैं, जो बताते हैं कि पक्षियों की बढ़ती या घटती गतिविधि एक अध्याय के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है। हम में से ज्यादातर लोग इस जुड़ाव को भूल चुके हैं, लेकिन कोई भी पक्षी प्रेमी सर्दियों के आखिरी नीरस दिनों में पक्षियों को रंग-बिरंगे रंग में रंगते देखने के उत्साह के बारे में जरूर बता देगा। जब पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपने पंख फड़फड़ाते हैं, तो मौसम में बदलाव की उम्मीद की जाती है।

ऊंचाई (कम ऊंचाई पर उड़ना बारिश का संकेत है, जबकि ऊंची उड़ानें अच्छे मौसम का संकेत देती हैं), उनकी आवाज (जैसे उल्लू का बोलना या मोर का नाचना बारिश का संकेत माना जाता है) और उनका भोजन व्यवहार (तूफान से पहले खूब खाना) शामिल है। कुछ ग्रामीण परंपराएं पक्षियों के घोंसले बनाने की जगह को भी मौसम का सूचक मानती हैं। उल्लू का चीखना और गौरैया का धूल में लोटना बारिश का संकेत माना जाता है। यदि कौवे कांटेदार पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, तो इसे बारिश कम होने की संभावना के रूप में देखा जाता है।

इसी तरह पक्षियों का आसमान में ऊंची उड़ान भरना अच्छे मौसम का संकेत होता है, यानी बारिश की कोई संभावना नहीं होती। जोड़े में उड़ने वाले कौवे भी अच्छे मौसम का संकेत देते हैं। इसी तरह तूफान से पहले पक्षी वसा जमा करने के लिए अधिक सक्रिय हो जाते हैं और खूब खाना खाते हैं। बारिश आने पर मुर्गियां बेचैन हो जाती हैं या धूल में खुद को रगड़ती हैं। हंस की छाती की हड्डी का लाल या गहरे रंग का होना ठंडी और तूफानी सर्दी का संकेत हो सकता है। यदि सारस आकाश में गोलाकार परावलय बना कर उड़ते हैं, तो यह शीघ्र वर्षा का संकेत है। पेड़ों पर दीमक का तेजी से घर बनाना अच्छी वर्षा का संकेत है। जब पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपने पंख फड़फड़ाते हैं, तो मौसम में बदलाव की उम्मीद की जाती है। वहीं चातक को बारिश का पक्षी माना जाता है। इसका आगमन मानसून के मौसम का संकेत है। इस तरह पशु-पक्षियों की हरकतों को देख कर मौसम का काफी हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

असल में यह हमारा पशु-पक्षियों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान है, जिसे हमारे पूर्वजों ने पूरा मान और सम्मान दिया है। मनुष्य लंबे समय से पशु-पक्षियों के व्यवहार को बदलते मौसमों के संकेतक के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। कई लोक कथाएं और किस्से हैं, जो बताते हैं कि पक्षियों की बढ़ती या घटती गतिविधि एक अध्याय के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है। हम में से ज्यादातर लोग इस जुड़ाव को भूल चुके हैं, लेकिन कोई भी पक्षी प्रेमी आपको सर्दियों के आखिरी नीरस दिनों में पक्षियों को रंग-बिरंगे रंग में रंगते देखने के उत्साह के बारे में जरूर बता देगा। सामान्य पक्षियों की तरह प्रवासी पक्षी भी कई अनुमान बताते हैं, जैसे 'मार्किंगबर्ड' और 'ब्लैकबर्ड' का रात भर चहचहाना बताता है कि गर्म दिन आने वाले हैं। कई प्रवासी पक्षी सर्दियों के आगमन अथवा जाने के बारे में इशारा करते हैं।

केवल पर्यावरण की बात करें, तो पक्षियों का अध्ययन पारिस्थितिकी संतुलन को समझने में मदद करता है, क्योंकि वे कीट नियंत्रण, परागण और बीज प्रसार में अहम भूमिका निभाते हैं। पक्षी पर्यावरण में हो रहे बदलाव के शुरुआती संकेत देते हैं। उनकी आबादी में गिरावट आवासों के क्षरण या जलवायु परिवर्तन का संकेत हो सकती है। पक्षी कीटों को नियंत्रित करते हैं, बीज फैलाते हैं और परागण में मदद करते हैं, जो मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई पौधों के लिए अहम है। पक्षी मृत जीवों और कचरे को साफ करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन उनके व्यवहार, प्रवास, प्रजनन और शारीरिक विशेषताओं को समझने में इंसान की पूरी तरह से मदद करता है। हमें केवल इस ज्ञान की समझ होने और इसके वैज्ञानिक प्रयोगों को पहचानने की जरूरत है।

Jansatta Page No-6

मप्र में वन्यजीवों की सुरक्षा को 'रेड कार्पेट'

शैलेन्द्र तिवारी • नईदुनिया

- **वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से गुजरे राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर एनएचएआइ ने किया प्रयोग**
- **वन्य जीव और वाहन चालकों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उठाया कदम**

नरसिंहपुर : भोपाल को जबलपुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-45 का एक हिस्सा इंजीनियरिंग और वन्यजीव संरक्षण का नया माडल बन गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होकर गुजरे हाईवे के करीब 12 किलोमीटर के इस हिस्से को टेबल टाप रेड मार्किंग तकनीक से सुरक्षित बनाया गया है। स्थानीय लोग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के इस नवाचार को रेड कार्पेट तकनीक कहते हैं।

दरअसल, राजमार्ग का यह हिस्सा पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। कई अंधे मोड़ भी हैं। वन्य प्राणियों की मौजूदगी भी यहां अक्सर बनी रहती है। हाईवे पर हादसे न हों, इसके लिए इसमें पांच मिमी मोटी लाल रंग की उभरी हुई मार्किंग की गई है, जिससे कोई वाहन गुजरता है तो हल्के झटके लगते हैं और वाहन की गति स्वतः नियंत्रित हो जाती है। ट्रक चालक आकाश ने कहा कि इससे दुर्घटना की आशंका भी कम हो गई

डोंगरगांव के पास एनएच-45 हाइवे में बनाई गई रेड मार्किंग का दृश्य। सौजन्य : इंटरनेट मीडिया

है। इसके अलावा यहां 25 अंडरपास बनाने के साथ चेन लिंक बाड़ लगाई गई है, ताकि वन्यजीव सड़क पर न आएं। रात में दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए दोनों किनारों पर पांच मिमी की वाइट शोल्डर लाइन बनाई गई है, जो वाहन किनारे जाते ही ड्राइवर को तेज झटका देकर सतर्क कर देती है। प्रोजेक्टर डायरेक्टर (एनएचएआइ) अमृत साहू ने कहा कि हाईपे पर गति नियंत्रक उपकरण स्थापित किए गए हैं। टेबल टाप रेड मार्किंग भी की गई है, जिससे सड़क देखने में सुंदर और सुरक्षित हो गई है। दुर्घटना का खतरा भी कम हो गया है।

Dainik Jagaran Page No-10

आत्मबल का सहारा

दुनिया मेरे आगे

राजेंद्र बज

जमाने की नजरों में हम कैसे हैं? यह जानने के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं। न ही कोई हमें यह समझा पाएगा कि हम कैसे हैं? दरअसल, बहुत संभव होता है कि कोई हमारे प्रति आग्रह या दुराग्रह रखे। ऐसी स्थिति में अपने आप से अपना वास्तविक परिचय जानने के लिए हमें अपनी अंतरात्मा को ही टटोलना होगा। अंतरात्मा की गवाही इस तथ्य की पुष्टि स्पष्ट रूप से कर सकेगी कि वास्तव में हम कैसे है? निश्चित रूप से जब हम अपनी पहचान कर लेते हैं, तब अंतर्मन में किसी प्रकार के बोझ से बाधित नहीं होते। जीवन एकदम सहज और सरल हो जाता है। हमारा यह स्वभाव एक प्रकार से हमारे व्यक्तित्व को शृंगारित करने लगता है।

हम क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे है? क्या कुछ हम कर चुके और क्या कुछ हम करना चाह रहे थे? आने वाले दौर में हम अपने आप को किस मुकाम पर लाकर खड़ा करना चाह रहे थे? क्या कुछ हम पा चुके और क्या खो चुके? अब तक की सारी जिंदगी जमाने भर की उठापटक में गुजर गई कि आखिरकार हमने क्या खोया और क्या पाया? इस तरह के तमाम सवालों का सही जवाब और किसी के एक सवाल का भी नहीं। मगर हमारी अपनी अंतरात्मा को बखूबी ज्ञात होता है। हालांकि जाहिर तौर पर हम अपने अंतर्मन की वास्तविक दशा और मनोदशा को खुलकर अभिव्यक्त नहीं करते। लेकिन हम क्या हैं, यह गवाही तो हमारा मन देता ही रहता है।

हमारा आचार-विचार और व्यवहार हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। इस दृष्टि से हर किसी के बारे में मतभिन्नता बहुत स्वाभाविक होती है। बहुत संभव होता है कि कोई किसी के लिए अच्छे से अच्छा हो और किसी के लिए बुरे से बुरा हो। ऐसी स्थिति में जब हम यह मूल्यांकन करना चाहें कि हम वास्तव में क्या हैं, तब स्वयं के बारे में निष्पक्ष तथा तटस्थ अवधारणा की पुष्टि हमारी अंतरात्मा ही करती है।

बहुत संभव होता है कि कोई किसी के लिए अच्छे से अच्छा हो और किसी के लिए बुरे से बुरा हो। ऐसी स्थिति में जब हम यह मूल्यांकन करना चाहें कि हम वास्तव में क्या हैं, तब स्वयं के बारे में निष्पक्ष तथा तटस्थ अवधारणा की पुष्टि हमारी अंतरात्मा ही करती है।

वास्तव में आदमी जमाने को धोखा दे सकता है और स्वयं भी धोखे में रह सकता है, लेकिन यह संभव नहीं कि कोई लंबे समय तक धोखे में रह सके। अंतरात्मा की गवाही नकारात्मक होने पर अपराधबोध और सकारात्मक होने पर आत्मबल में वृद्धि करती है।

दरअसल, व्यक्ति विशेष के अंतरंग और बहिरंग में एकरूपता हो, ऐसी अपेक्षा की जाती है, लेकिन इस अपेक्षा की कसौटी पर हर कोई खरा उतर सके, यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति विशेष के प्रति आम धारणा चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह धारणा पूर्ण रूप से सकारात्मक या पूर्ण रूप से नकारात्मक भी हो सकती है। आजकल के जमाने में सर्वमान्य शख्सियत की परिकल्पना दिवास्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। यह बहुत संभव होता है कि नकारात्मक व्यक्ति के पक्ष में कुछ सकारात्मक बिंदु भी हों। ठीक इसी तरह सकारात्मक में भी नकारात्मकता के अंश को खोजा जा सकता है।

गरज यह कि इस संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं है। सामान्य बोलचाल में भी कहा गया है कि लोगों ने राजा राम को नहीं छोड़ा तो आप हम क्या है! ऐसी स्थिति में यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने स्तर पर एकदम सही रहें। हमारा सकारात्मक सोच-विचार तथा कार्य और व्यवहार पूर्ण रूप से सात्विक रहे। एक अर्थ में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को हम खुद ही समय-समय पर तटस्थ एवं निष्पक्ष रूप से आकलित कर प्रमाणित करते रहें। यही आत्म-मूल्यांकन का सिलसिला हमारे अपने अंतर्मन की संतुष्टि का अहम कारण बन सकता है। इससे आत्मबल में वृद्धि होती है, जिसके चलते जीवन संवर जाता है।

हमारा हाव-भाव और व्यवहार भी जमाने भर को हमारे व्यक्तित्व एवं कृतित्व के मूल्यांकन का आधार देता है। चित्त की सहजता और सरलता के मनोभाव आचार-विचार और व्यवहार से परिलक्षित होते हैं। इसके अलावा, चित्त की कुटिलता का आकलन भी प्रयुक्त शब्दावली और भाव-भंगिमा के आधार पर सहज ही किया जा सकता है। दरअसल, इस सहज मनोविज्ञान को औसत स्तर के आम व्यक्ति के लिए भी समझना कोई दुष्कर नहीं है। यह निश्चित है कि जब हम सहज और सरल होते हैं, तो हमारा आत्मबल अत्यंत विकसित अवस्था में आकर सकारात्मक वातावरण का सृजन करने में प्रबल रूप से सहायक होता है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारे अपने आसपास के परिवेश में, जान-पहचान के लोगों के बीच हमारे व्यक्तित्व एवं कृतित्व को लेकर आमतौर पर कोई न कोई धारणा अवश्य होती है। यह धारणा केवल नकारात्मक या केवल सकारात्मक ही हो, यह कतई आवश्यक नहीं होता। ऐसा भी होता है कि जमाने की निगाहों में हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति मिली-जुली धारणा हो। ऐसी स्थिति में कभी-कभी हमें संदेह का लाभ भी मिल जाया करता है। दरअसल, इस संसार में कोई भी व्यक्ति हर एक दृष्टि से परिपूर्ण नहीं हो सकता। हर किसी के व्यक्तित्व और कृतित्व के आकलन में परस्पर विरोधाभास की स्थिति बहुत स्वाभाविक होती है।

ऐसी स्थिति में हमें अपने प्रति जनमानस में व्याप्त सकारात्मक या नकारात्मक धारणा को लेकर न तो उत्साहित होना चाहिए और न ही निराश। हर किसी के लिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व का आकलन करने के अपने अलग-अलग पैमाने हुआ करते हैं। उसके आधार पर किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। इन तमाम संदर्भों में हमें हमारे अंतर्मन की आवाज सुनने और सुनते रहने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम अपने स्तर पर अपनी जगह अगर सही हैं, तो जमाने की विपरीत हवा भी कभी हमारा अहित नहीं कर सकेगी।

अराजकता का मैदान

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कोई खिलाड़ी अगर किसी आयोजन के तहत लोगों के बीच जाता है, तो उम्मीद की जाती है कि वहां हर स्तर पर चाक-चौबंद व्यवस्था होगी। कार्यक्रम का स्वरूप पूरी तरह ठोस और मुकम्मल होगा तथा सुरक्षा-व्यवस्था में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मगर कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यात फुटबाल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी जब पहुंचे, तो आयोजकों की अदूरदर्शिता और अव्यवस्था की वजह से वहां व्यापक अराजकता फैल गई। यह हैरानी की बात इसलिए है कि लियोनेल मेस्सी की लोकप्रियता और उनके प्रशंसकों के बीच उन्हें देखने को लेकर दीवानगी के बारे में तस्वीर पहले ही साफ थी। फिर मेस्सी के कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी क्यों बनाई गई, जिसकी वजह से उन्हें देखने आए लोगों के बीच आक्रोश भड़का। गौरतलब है कि मेस्सी अपने भारत दौरे के क्रम में कोलकाता आए थे और वहां स्टेडियम में वे अपने प्रशंसकों से मिलने गए थे। मगर वहां उनके आसपास कई नेता और अन्य लोग इस तरह मौजूद थे कि वे एक तरह से वहां गुम हो गए और दर्शकों के लिए उन्हें देखना मुश्किल हो गया। इस पर लोगों के भीतर गुस्सा पैदा हुआ और उन्होंने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। आखिर मेस्सी को वहां से बाहर निकलना पड़ा।

सवाल है कि आयोजकों ने इस बात को क्यों भुला दिया कि वहां स्थानीय से लेकर बाहर से बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मेस्सी को सिर्फ देखने के लिए अगर पांच हजार से पच्चीस हजार रुपए तक की टिकट खरीदी है, तो वादे के अनुरूप व्यवस्था का ध्यान रखा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर लोगों के धीरज खोकर अराजक होने को उचित नहीं कहा जाएगा, लेकिन यह भी तथ्य है कि आयोजकों की लापरवाही की वजह से स्टेडियम में अराजकता छाई, जिसका अंजाम त्रासद भी हो सकता था। इस घटना के बाद स्वाभाविक ही वहां की कानून-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अगर आयोजन और वहां पहुंचे लोगों के मकसद को ध्यान में रख कर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती और एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने का इंतजाम किया जाता, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती।

Jansatta Page No-6

रोजगार के अवसर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा गांवों के अकुशल लोगों के लिए काम पाने और अपनी आजीविका चलाने का एक बहुत बड़ा सहारा है। अगर किसी ग्रामीण को और कहीं काम न मिले तो वह मनरेगा के तहत रोजगार पा सकता है। इस कानून के तहत सौ दिन के कार्य की गारंटी दी गई है। केंद्र सरकार ने अब इन कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर एक सौ पच्चीस करने का फैसला किया है और इससे संबंधित विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। मगर इसे अब मनरेगा नहीं बल्कि 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना' के नाम से जाना जाएगा। यानी अब इसके नए स्वरूप में काम की गारंटी होगी या नहीं, इसको लेकर अभी आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं है। मगर कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय देश की ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के लिहाज से एक महत्त्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आज भी रोजगार का अभाव है और अगर सौ दिन काम मिल भी जाए, तो उसके पारिश्रमिक से घर-परिवार चलाना व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल है।

यह दूसरी बार है, जब इस कानून या योजना का नाम बदला गया है। इसे वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के नाम से लागू किया गया था। इसके बाद वर्ष 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। अब उसके कार्य दिवस में बढ़ोतरी की पहल स्वागतयोग्य है, लेकिन यह सही मायने में तभी सफल मानी जाएगी, जब इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। इसमें दोराय नहीं कि कोविड महामारी के दौरान जब कई उद्योग-धंधे बंद हो गए और हजारों लोग बेरोजगार हुए, तो इसी योजना ने ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहारा दिया था। देश भर में करोड़ों परिवारों की आजीविका का एक हिस्सा इस योजना पर टिका हुआ है।

ग्रामीण इलाकों में इस रोजगार योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर पहले से चुनौतियां कम नहीं हैं। शुरुआत से ही इसे लेकर कई तरह की अनियमितताओं के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें गारंटी के मुताबिक सौ दिन का रोजगार न मिलना, कागजों में फर्जी तरीके से रोजगार देना और वित्तीय गड़बड़ियां प्रमुख हैं। अब काम के दिनों में बढ़ोतरी तभी सार्थक होगी, जब पुरानी गड़बड़ियां और अनियमितताओं को दूर किया जाए। ऐसे में इस योजना की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। एक अन्य चुनौती आर्थिक बजट की है, सरकार पर इस योजना के लिए धन आबंटन में कटौती के आरोप भी लगते रहे हैं। हालांकि, सरकार का तर्क है कि यह मांग आधारित योजना है और मांग बढ़ने पर धनराशि का आबंटन भी बढ़ाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम के दिन बढ़ाने के सरकार के निर्णय को इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि अगर रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित किए जाएं, तो गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराने जैसी योजनाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से ज्यादा जरूरी है कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

कोविड टीकाकरण और अचानक मृत्यु के बीच वैज्ञानिक संबंध नहीं

जनसत्ता विशेष

भारत के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए व्यापक अध्ययनों में कोविड-19 टीकाकरण और वयस्कों, विशेष रूप से 18-45 आयु वर्ग के लोगों में अचानक मृत्यु के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया है। एम्स सहित भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अध्ययनों से यह पुष्टि हुई है कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण और युवा वयस्कों में अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई सीधा वैज्ञानिक संबंध नहीं है। ये मौतें आनुवंशिकी, जीवनशैली, या कोविड-19 के बाद की जटिलताओं जैसी अन्य वजहों से हो सकती हैं, और टीके सुरक्षित व प्रभावी हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ये निष्कर्ष भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एआइआइएमएस), नई दिल्ली द्वारा किए गए विस्तृत शोध पर आधारित हैं।

शोध

कोविड-19 महामारी के बाद अचानक और अस्पष्ट मौतों को लेकर बढ़ती जन चिंता के बीच इन अध्ययनों की शुरुआत की गई थी। हालांकि, शोध परिणामों ने टीकों और ऐसी मौतों के बीच किसी भी प्रत्यक्ष संबंध को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। इसके बजाय, वे पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों, आनुवंशिक कारकों, जीवनशैली विकल्पों और कुछ मामलों में, कोविड-19 के बाद की जटिलताओं के संयोजन को अंतर्निहित कारणों के रूप में इंगित करते हैं। आइसीएमआर के राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (एनआइई) द्वारा किए गए प्रमुख अध्ययनों में से एक, 'भारत में 18-45 वर्ष की आयु के वयस्कों में अज्ञात कारणों से होने वाली अचानक मृत्यु से जुड़े कारक' शीर्षक से एक बहुकेंद्रीय मिलानित केस-कंट्रोल अध्ययन था। मई और अगस्त 2023 के बीच किए गए इस अध्ययन में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 तृतीयक देखभाल अस्पताल शामिल थे। इसमें उन मामलों की जांच की गई जिनमें स्वस्थ दिखने वाले व्यक्तियों की अक्तूबर 2021 और मार्च 2023 के बीच अचानक मृत्यु हो गई। परिणामों में कोविड-19 टीकाकरण के बाद अज्ञात कारणों से होने वाली अचानक मृत्यु के जोखिम में कोई वृद्धि नहीं पाई गई।

इसी क्रम में, एम्स नई दिल्ली, आइसीएमआर के सहयोग से युवाओं में अचानक होने वाली अज्ञात मौतों के कारणों का पता लगाना शीर्षक से एक भावी अध्ययन कर रहा है। हालांकि अध्ययन अभी जारी है, प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि 'मायोकार्डियल इन्फार्क्शन' (दिल का दौरा) युवा वयस्कों में अचानक होने वाली मौतों का प्रमुख कारण बना हुआ है। कारणों का तरीका पिछले वर्षों के रुझानों के अनुरूप ही बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, कई मामलों में, आनुवंशिक उत्परिवर्तन को भी एक सहायक कारक के रूप में पहचाना गया है।

दोनों अध्ययनों के निष्कर्ष सामूहिक रूप से युवा वयस्कों में अचानक होने वाली मौतों की ठोस वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और भारत में लगाए गए कोविड-19 टीकों की सुरक्षा को पुष्ट करते हैं। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि टीकों को ऐसी मौतों से जोड़ने वाली गलत सूचना या अपुष्ट दावे न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत हैं, बल्कि टीकाकरण कार्यक्रमों में जनता के विश्वास के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अटकलबाजी और निराधार दावों को फैलाने से टीकाकरण के प्रति हिचकिचाहट बढ़ सकती है। एक ऐसा परिणाम जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों को कमजोर कर सकता है और महामारी के प्रबंधन में हुई प्रगति को उलट सकता है।

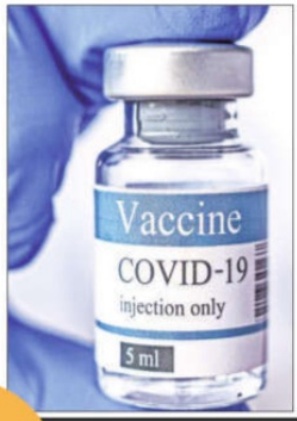

दिल्ली के एम्स में किए गए एक व्यापक, एक वर्षीय शव परीक्षण-आधारित अवलोकन अध्ययन में कोविड-19 टीकाकरण और युवा वयस्कों में अचानक मृत्यु के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया है, जो कोविड टीकों की सुरक्षा की पुष्टि करता है।

अध्ययन में कहा गया है कि युवा वयस्कों में अचानक मृत्यु एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है जिसके लिए लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों की आवश्यकता है, अंतर्निहित कोरोनरी धमनी रोग इसका प्रमुख कारण बना हुआ है और श्वसन संबंधी और अस्पष्टीकृत मौतों की आगे जांच की जानी चाहिए।

शोध परिणामों ने टीकों और ऐसी मौतों के बीच किसी भी प्रत्यक्ष संबंध को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। इसके बजाय, वे पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों, आनुवंशिक कारकों, जीवनशैली विकल्पों और कुछ मामलों में, कोविड-19 के बाद की जटिलताओं के संयोजन को अंतर्निहित कारणों के रूप में इंगित करते हैं।

Jansatta Page No-7

केंद्र की देरी से जमीन तक नहीं पहुंच पा रही अमृत योजना

पंकज रोहिला

शहरों में पेयजल – सीवर योजनाओं को लागू करने के लिए शुरू की गई अमृत योजना के लिए राज्यों को वक्त पर पैसा नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार का यह हिस्सा नहीं मिल पाने की वजह से ये योजनाएं बीच में फंसी हैं। अमृत और अमृत – 2 के तहत शुरू की गई योजनाओं को लेकर जारी रपट में यह बात सामने सामने आई है। इस पर हाल ही में संसदीय समिति ने चिंता दर्ज कराई है और कहा है कि इस लापरवाही की वजह से पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने में लगातार देरी हो रही है। हालांकि रपट में सरकार ने खुद दावा किया है कि देश में आगामी 2030 तक शहरी क्षेत्रों में पानी की मांग दो गुना तक बढ़ सकती है।

रपट

रपट में यह भी सामने आया है कि दुनिया के बीस सबसे अधिक जल संकटग्रस्त शहरों में से पांच भारत में हैं और इन शहरों में दिल्ली भी शामिल है, जो कि वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त भारत में 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 80 लाख बच्चे स्वास्थ्य और स्वच्छता संबगंधित कमियों के कारण जोखिम में हे। ऐसे ही जोखिमों को कम करने के लिए अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की शुरुआत की गई थी। इसके तहत पांच सौ चुनिंदा शहरों में 65 फीसद शहरी आबादी के लिए कार्य करना था और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर जल, सीवर समेत अन्य योजनाओं को लागू करना था।

रपट बताती है कि अमृत एक योजना के तहत 83550 करोड़ रुपए की थी, इस योजना में 77640 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इस लागत से कुल 6010 परियोजनाओं को शुरू किया गया है और 95 फीसद भौतिक कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। कुल राशि में अब तक भी केवल 87 फीसद धनराशि का ही प्रयोग किया गया है। अभी भी इस योजना के तहत स्वीकार की गई 4073 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। इन योजनाओं को अमृत दो योजना के तहत शामिल किया गया था, जो पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने में लगातार देरी को दर्शाता है। अमृत मिशन के तहत कुल 4.68 करोड़ घरों तक नल से पानी और सीवर सेवाओं का विस्तार 31 से 62 फीसद करना था।

केंद्र सरकार ने अमृत दो के तहत लगभग 1.90 करोड़ रुपए की 8791 परियोजनाओं को मंजूरी दी दी है। रपट बताती है कि इन परियोजनाओं में से केवल 1.54 लाख करोड़ की विस्तृत कार्य योजना (डीपीआर) तैयार किए गए हैं और 1.47 लाख करोड़ रुपए के लिए निविदा (एनआइटी) व 1.18 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध दिए गए हैं। लेकिन भौतिक कार्य केवल 48050 करोड़ रुपए का ही है। जबकि व्यय केवल 35520 करोड़ रुपए का ही हुआ है। जो कि विभिन्न परियोजनाओं में प्रक्रियात्मक अड़चनों और धीमी जमीनी प्रगति का दर्शाता है। इसके अतिरिक्त अब तक केवल 12724 करोड़ रुपए ही जारी किए गए है, जो कि केंद्रीय हिस्से का केवल 19 फीसद है। ये पैसा नहीं मिलने की वजह से राज्यों व निकायों का योगदान को हतोत्साहित कर सकता है। समिति ने यह भी साफ कहा कि इस परियोजनाओं को लेकर राज्यवार आवंटन में काफी असमानताएं सामने आई है।

आवासन ओर शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति ने संसद से सिफारिश की है कि समिति ने जनसंख्या परिवर्तन के मद्देनजर 2050 तक भारत की आधी से अधिक आबादी का शहरों में रहने का अनुमान जताया है और कहा है कि यह भी सवाल किया है कि यहां बढ़ने वाली आबादी के लिए केंद्र सरकार ने क्या दीर्घाकालीन समय के लिए शहरी पेयजल की मांग का अनुमान लगाने के लिए कोई व्यापक मूल्यांकन किया है। समिति ने सिफारिश की है कि बढ़ती मांग की स्थिति को देखते हुए अगले 25 से 30 वर्ष के लिए शहरी पेयजल की मांग का एक एकीकृत राष्ट्रीय स्तर का आकलन ओर अनुमान तत्काल शुरू किया जाए। इसके निष्कर्ष को एक राष्ट्रीय शहरी जल सुरक्षा नीति का आधार बनाया जाना चाहिए जो भविष्य में जल सुरक्षित शहरों को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

Jansatta Page No-7

डा. अमरजीत कुमार
शिक्षा मामलों के जानकार

आजकल

उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का संकेत

संसद के वर्तमान सत्र में केंद्र सरकार विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक (पूर्व में उच्च शिक्षा आयोग बिल) प्रस्तुत करने की तैयारी में है जो वर्तमान प्रणाली में सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने जिस एकीकृत नियामक माडल की कल्पना की थी, यह बिल उसी विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य यूजीसी की जगह एक ऐसे आयोग की स्थापना करना है जो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरी नियामक जिम्मेदारियों को एकीकृत करे और पूरे देश में उच्च शिक्षा के लिए स्पष्ट, समान और प्रभावी ढांचा तैयार करे

उच्च शिक्षा से जुड़े सभी नियामकों को एकीकृत करने से मजबूत होगी उच्च शिक्षा व्यवस्था। फाइल

भारत की उच्च शिक्षा में अभी कई अलग-अलग संस्थाएं काम करती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के नियमन और मानकों को तय करता है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद बनी हुई है, जबकि शिक्षण व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद नियंत्रित करती है। यह तीन ध्रुवीय व्यवस्था कई बार छात्रों, शिक्षकों और विवि को एक साथ कई संस्थाओं से अनुमति लेने और नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करती है। किसी नए कोर्स, विभाग या कार्यक्रम को शुरू करने के लिए कालेजों को अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे समय और ऊर्जा की हानि होती है।

नई शिक्षा नीति ने इन समस्याओं का विश्लेषण किया और कहा कि वर्तमान ढांचा बिखरा हुआ है और इसे पूरी तरह नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता है। इसी विचार के अनुरूप प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग को एक व्यापक संस्था के रूप में देखा जा रहा है, जो नियमन, मान्यता, अकादमिक मानकों और अनुदान जैसे चार बड़े क्षेत्रों में स्पष्ट भूमिकाओं के साथ एक सुव्यवस्थित प्रणाली प्रदान करेगा। इस आयोग के चार स्तंभों की रूपरेखा पहले ही नीति में रखी जा चुकी है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद को उच्च शिक्षा के सभी क्षेत्रों की निगरानी का कार्य सौंपा जाएगा। राष्ट्रीय मान्यता परिषद संस्थानों की गुणवत्ता को परखने की जिम्मेदारी संभालेगी। सामान्य शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम, अधिगम परिणाम और राष्ट्रीय अकादमिक मानकों को तय करेगी।

यह संरचना इस विचार पर आधारित है कि एक ही संस्था के भीतर एक-दूसरे से जुड़े क्षेत्रों को अलग-अलग खंडों में विभाजित किया जाए, ताकि नीति बनाते समय पारदर्शिता, सुगमता और विशेषज्ञता सुनिश्चित की जा सके। मौजूदा ढांचे में अक्सर यह देखा गया है कि कई संस्थाएं एक ही विषय में अधिकार जताती हैं, जिस कारण भ्रम और देरी पैदा होती है। नई व्यवस्था इस दोहराव को रोकने पर जोर देती है। यह उम्मीद की जा रही है कि एकीकृत आयोग के आने से विश्वविद्यालयों को अनुमति लेने की प्रक्रिया सरल होगी और वे अपने शैक्षणिक कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। हालांकि यह विचार नया नहीं है। सरकार ने 2018 में भी उच्च शिक्षा आयोग का एक प्रारूप तैयार किया था, जिसका उद्देश्य यूजीसी को बदलना था। उस समय हालांकि एआइसीटीई और एनसीटीई को आयोग में शामिल नहीं किया गया था और आयोग को केवल अकादमिक मानकों से जुड़े अधिकार देने की बात की गई थी। इस प्रारूप में अनुदान की शक्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास ही रहती, जिससे यह आशंका पैदा हुई थी कि विश्वविद्यालय वित्तीय रूप से मंत्रालय पर अधिक निर्भर हो जाएंगे। प्रारूप सामने आते ही कई शिक्षाविदों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों ने अति-नियमन की चिंता जताई थी। कई लोगों ने यह भी कहा था कि आयोग में विविध सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। विरोध के बाद प्रारूप वापस लिया गया।

नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सरकार ने अब फिर से इस विचार को रूपांतरित किया है। इस बार प्रस्ताव में तकनीकी और शिक्षण व्यवस्था दोनों को एक ही ढांचे में शामिल किया गया है, जो पहले संभव नहीं हो सका था। यही कारण है कि वर्तमान बिल को अधिक व्यापक और संतुलित माना जा रहा है। शिक्षा मंत्री कई बार यह कह चुके हैं कि यह आयोग दूसरी पीढ़ी के सुधारों का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसका उद्देश्य एक जवाबदेह नियामक प्रणाली का गठन करना है।

फिर भी इस प्रस्ताव को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एक ही संस्था में अत्यधिक शक्ति केंद्रित होने का खतरा हमेशा रहता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इससे उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता तय होगी। कुछ राज्यों ने भी चिंता जताई है कि यदि अनुदान मंत्रालय के माध्यम से दिया जाएगा तो राज्य विश्वविद्यालयों को अपने विकास के लिए केंद्रीय संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ सकता है। एक संसदीय समिति ने भी चेतावनी दी थी कि अत्यधिक केंद्रीकरण से राज्य विश्वविद्यालयों को दोहरे नियमों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उन्हें केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों का पालन करना पड़ेगा।

इसके बावजूद यह सच है कि भारत की उच्च शिक्षा तेजी से बढ़ती आबादी और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही है। देश में एक हजार से अधिक विश्वविद्यालय और 50 हजार से अधिक कालेज हैं, परंतु कई संस्थाएं अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता हासिल नहीं कर पाई हैं। मान्यता की प्रक्रिया कई बार धीमी और अस्पष्ट रहती है, जिससे शिक्षण संस्थान अपने सुधारों को समय पर आगे नहीं बढ़ा पाते। इसके अलावा, विभिन्न नियामक संस्थाओं के बीच सामंजस्य का अभाव भी कई बार नीतिगत टकरावों को जन्म देता है। इसी कारण एक ऐसी संस्था की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी जो पूरे ढांचे को व्यवस्थित कर सके।

अकादमिक स्वतंत्रता की संभावना : यदि नया आयोग सफलतापूर्वक गठित होता है, तो विश्वविद्यालयों के लिए अनुमति और मान्यता की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। उन्हें अलग-अलग संस्थाओं के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे समय की बचत होगी और विश्वविद्यालय अपने शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। पाठ्यक्रमों और शिक्षण परिणामों के लिए निर्धारित किए जाने वाले राष्ट्रीय मानक पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता को एक समान बनाने में मदद करेंगे।

नई व्यवस्था से विश्वविद्यालयों को अधिक अकादमिक स्वतंत्रता मिलने की संभावना है, परंतु साथ ही गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अधिक जिम्मेदार भी होना पड़ेगा। संस्थानों को अपने संसाधन, शिक्षक क्षमता, अनुसंधान कार्य और शिक्षण व्यवस्था पर अधिक ध्यान देना होगा। यह बदलाव आसान नहीं होगा, क्योंकि मान्यता और नियामक प्रक्रियाओं के स्थानांतरण में समय लगेगा। विश्वविद्यालयों को नए मानकों और प्रक्रियाओं को समझने और अपनाने में कई वर्ष लग सकते हैं, लेकिन इन बदलावों के लाभ अधिक बड़े होंगे।

भारत विश्व मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनुसंधान, नवाचार और मानव संसाधन विकास किसी भी देश की प्रगति की आधारशिला हैं। ऐसे समय में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना आवश्यक है। उच्च शिक्षा आयोग का प्रस्ताव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल प्रणाली को सरल बनाएगा, बल्कि देश की उच्च शिक्षा को अधिक पारदर्शी, सक्षम और गुणवत्तापूर्ण बनाने में भी मदद करेगा। अंततः यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि नया बिल संसद में किस दिशा में आगे बढ़ता है और किस रूप में पारित होता है।

गुणवत्ता सुधारने की दिशा में सार्थक प्रयास

उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना को लेकर प्रस्तावित मसौदे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जैसी संस्थाओं की नियामक भूमिकाओं को एकीकृत करेगा। वर्तमान में विभिन्न लगभग 14 शैक्षणिक क्षेत्र हैं जिनके लिए पहले से अलग नियामक निकाय मौजूद हैं। ऐसे में शिक्षण संस्थानों को सभी नियामकों से मान्यता लेना अनिवार्य होता है। महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए बने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) ने वर्ष 2009 में और यशपाल समिति ने 2010 में उच्च शिक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा करते हुए परिषदों और नियामक संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। दोनों समूहों ने माना था कि देश की उच्च शिक्षा प्रणाली कई परिषदों और नियामक संस्थाओं में बंटी हुई है, जिससे दोहराव और भ्रम पैदा होता है। एनकेसी ने यहां तक कहा था कि चिकित्सा और विधि शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी पेशेवर परिषदों को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि उच्च शिक्षा का ढांचा सरल, पारदर्शी और प्रभावी हो सके।

समिति का सुझाव था कि पेशेवर परिषदों की भूमिका केवल पात्रता परीक्षाएं आयोजित करने तक सीमित की जाए, जबकि सामान्य शिक्षा का पूरा नियमन एक ही शीर्ष संस्था द्वारा किया जाए। यशपाल समिति ने भी इसी तरह एक समग्र उच्च शिक्षा आयोग बनाने का सुझाव दिया था, ताकि विश्वविद्यालयों पर अनावश्यक दबाव, नियंत्रण और नियामक विसंगतियों को कम किया जा सके। समिति ने उच्च शिक्षा में एकीकृत मानकों और स्वतंत्रता की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसी पृष्ठभूमि में उच्च शिक्षा आयोग का प्रस्ताव आगे बढ़ा, जिसने अब सामान्य विषयों वाले विवि और कालेजों को एक ही ढांचे के अंतर्गत लाने का रास्ता साफ किया है।

उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना को लेकर प्रस्तावित प्रारूप में चिकित्सा और विधि शिक्षा इसके दायरे से बाहर रहेंगी। इसका अर्थ है कि चिकित्सा शिक्षा का नियमन पूर्व की तरह मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआइ) और विधि शिक्षा का नियमन बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) ही करते रहेंगे। गौरतलब है कि चिकित्सा और विधि शिक्षा अत्यंत विशिष्ट और संवेदनशील क्षेत्रों में आती हैं, जिनके लिए अलग नियामक तंत्र की आवश्यकता है। नई व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में प्रयास जारी हैं। हालांकि चिकित्सा और विधि शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक तंत्र बना रहेगा, पर बाकी सभी उच्च शिक्षा क्षेत्रों में एकीकृत ढांचा लागू होने की संभावना है। यह देखा जाएगा कि प्रस्तावित आयोग उच्च शिक्षा को किस तरह नई दिशा देता है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नियामक ढांचों के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाता है।

(डा. अमरजीत कुमार)

खरी-खरी

पुरस्कार बीमार है

राजेंद्र कुमार सिंह

राजनीतिक गलियारों में पुरस्कार का कारोबार आज एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जो योग्य है उसको नकार दो और भले ही अयोग्य हो, लेकिन इसके पीछे जमात हो जिसका समाज में वर्चस्व हो, उसको पुरस्कार देकर अपने भविष्य को सवार लो।

कभी एक पुरस्कार पाकर कितना खुश होते थे। आज कोई किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, पुरस्कार सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन आज किसी भी क्षेत्र की बात की जाए तो पुरस्कार आज कूड़े के ढेर की तरह किसी कोने में पड़ा हुआ मिल जाएगा। खासकर साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में पुरस्कार का कचूमर निकाल दिया गया है।

आज देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि पुरस्कार की दुर्गति निकल गई है। कभी यही पुरस्कार सद्गति, सौहार्द, उपकार, मृदुल व्यवहार तथा जिस क्षेत्र का पुरस्कार है, उस पर एकाधिकार या आधिपत्य स्थापित हो। तब हर तरफ से सोच-विचार कर समिति की सलाह पर पुरस्कार का निर्वाह होता था या निर्गत किया जाता था। आज जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, वह अपने फायदे के लिए कायदे को ताक पर रखकर या साख को नीलाम कर पुरस्कार को भी बदनाम किया जा रहा है।

एक पुरस्कार है, जिसे अपने फायदे के लिए ऐसे नेता को दिया गया है, जिसकी पार्टी को जीवन भर उसके दल की ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखा गया। उस पार्टी ने उस व्यक्ति को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसी पार्टी के द्वारा पुरस्कार से नवाजा जाएगा, क्योंकि उसके चलते उसका समाज पार्टी का कृतज्ञ रहेगा।

साहित्य के पुरस्कार का भी बंटाधार हो गया है। ऐसे लोगों के नाम की घोषणा हो रही है कि पुरस्कार भी हंसने लगा है। पुरस्कार पर जिसका अधिकार होना चाहिए, वह तो लाचार है और जो दुराचार में लिप्त है, आज उसी के यहां शिफ्ट हो रहा है। सरकार भी संस्कार को पीछे धकेल ऐसे बकलोल को देकर खेल कर रही है, जिससे पुरस्कार भी बार-बार अपने को आहत हो राहत मांग रही है। यह देख सम्मान भी दिन-प्रतिदिन अपनी दुर्गति देख पंगु हो गया है या यूं कहें पुरस्कार भी आज बीमार चल रहा है।

मंथन

डा. नवीन कुमार मिश्र
भू-राजनीतिक मामलों के जानकार

विश्व में बढ़ती भारत की भूमिका

रूस के साथ फिर से बढ़ती निकटता के बीच भारत को दक्षिण एशिया में उभरे हालात को कूटनीतिक रूप से नियंत्रित करना होगा। इससे वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ सकता है

भारत-अमेरिका संबंधों में तेजी से आ रही गिरावट की पृष्ठभूमि में रूसी नेता की नई दिल्ली यात्रा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पहली बार ऐसे समय हुई है, जब प्रतिबंधों और अमेरिकी दबाव के कारण रूस की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार पर अंकुश लग रहा है। रूस के साथ दशकों पुरानी द्विपक्षीय साझेदारी भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद मजबूत व स्थिर संबंध रक्षा जरूरतों, व्यापार को बढ़ाने तथा छोटे माड्यूलर रिएक्टरों में सहयोग की संभावनाओं पर पश्चिमी देशों की भी करीबी नजर के बीच इस यात्रा के माध्यम से रूस यह दिखाने में सफल रहा कि मास्को के अभी भी पश्चिम से अलग मजबूत रिश्ते और बड़े बाजार मौजूद हैं। दूसरी तरफ एक स्वतंत्र रणनीतिक राह बनाने की निरंतर क्षमता को प्रदर्शित करने के साथ अमेरिका को संदेश है कि भारत के अन्य आर्थिक व रक्षा साझेदार हैं।

पिछले दो दशकों में भारत रूस से दूर और पश्चिम के करीब पहुंच गया। ट्रंप के पहले कार्यकाल में संबंध और मजबूत हुए। परंतु दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से तेल खरीदने व भारत-पाकिस्तान युद्ध की मध्यस्थता को भारत द्वारा नकारे जाने से नाराज होकर भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। भारत ने इसका सार्वजनिक जुबानी विरोध नहीं किया, परंतु ट्रंप के कारण बढ़ते अविश्वास से भारत का रूस व चीन के करीब जाना वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के संकेत देता है। एक तरफ वैश्विक गठबंधन टूटते व छूटते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नए संगठनों के उभार की शुरुआत भी हो रही है।

रणनीतिक चुनौतियां : चीन ने सदैव भू-राजनीतिक व रणनीतिक चुनौतियां भारत के समक्ष प्रस्तुत की हैं। पिछले दो दशकों में भारत अमेरिका के बहुत करीब आ गया और यह बदलाव चीन के आर्थिक एवं सैन्य उदय पर इनकी साझा चिंताओं के कारण ही हुआ। परंतु भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में बढ़ती प्रगति में रुकावट से ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका रणनीतिक बदलाव करते हुए अपना ध्यान हिंद-प्रशांत क्षेत्र और चीनी शक्तियों पर नियंत्रण से हटा लिया है और हिंद-प्रशांत में भारत की भूमिका का महत्व कम हो गया है। परंतु अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 में स्पष्ट हुआ है कि एक हिंद-प्रशांत क्षेत्र अमेरिकी समृद्धि और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु इस क्षेत्र में बदली हुई रणनीति के तहत अमेरिका अब चीन के साथ टकराव की स्थिति में नहीं रहने वाला है।

भारत में यह धारणा थी कि पिछले 25 वर्षों से चली आ रही रूस और चीन के साथ अमेरिकी प्रतिद्वंद्विता विश्व राजनीति के केंद्र में रहने वाला है। इसके अलावा, भारत रूस के साथ अमेरिकी मेल-मिलाप पर सकारात्मक व उसका पक्षधर तो रहा है, परंतु चीन के प्रति ट्रंप के सुलह के प्रयास राष्ट्र के लिए चिंता व चुनौतियों को खड़ा करने वाला है। भू-राजनीतिक रूप से अमेरिका भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीति का प्रमुख आधार तो मानता है, परंतु उसके हितों की अनदेखी कर आर्थिक चोट भी पहुंचाता है।

इन परिस्थितियों में भारत के पास एशियाई भू-राजनीति को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का एक अवसर दिखाई पड़ता है। इसके तहत भारत को वर्तमान कठिन परिस्थितियों के बावजूद अमेरिका के साथ निरंतर संपर्क व संवाद बनाए रखने की आवश्यकता है।

भारत और रूस की प्रगाढ़ मित्रता विश्व को नई चुनौती देने में सक्षम साबित हो सकती है। फाइल

दशकों से चीन के साथ भारत की सीमा अस्थिर रही है। वर्तमान में चीन के साथ संबंधों को स्थिर करने के लिए सक्रिय प्रयास करने होंगे और एससीओ के शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात उसी कड़ी का हिस्सा है। भारत को अमेरिका और चीन ही नहीं, बल्कि यूरोप और रूस दोनों के साथ संबंध मजबूत कर उसमें स्थिरता लानी पड़ेगी। भारत को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों तथा आस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी को और सुदृढ़ करना होगा।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पुरानी व्यवस्था को नष्ट करने के बाद वह एक नया वैश्विक ढांचा कैसे तैयार करेंगे, यह तय नहीं है। इनकी रणनीति में राष्ट्र-राज्यों के बीच शांति स्थापित कर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को कायम करना चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ता है। इसलिए भारत को रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता पर जोर देते हुए सबसे बड़े रक्षा आपूर्तिकर्ता रूस और व्यापारिक सहयोगी अमेरिका के बीच संतुलन बनाते हुए अपने हितों के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत के लिए यह चुनौती है कि इन समानांतर भूमिकाओं का लाभ उठाकर बिना किसी गठबंधन में उलझे यह तय करना पड़ेगा कि भारत वैश्विक शासन के अगले चरण को कितने प्रभावी ढंग से आकार दे पाता है।

काम और जीवन के बीच संतुलन का सवाल

वेंद्रराज सुथार

राइट टू डिस्कनेक्ट मानव गरिमा, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन के अधिकार से जुड़ा प्रश्न है

डिजिटल तकनीक के विस्तार और कार्य संस्कृति में आए बदलावों के साथ 'राइट टू डिस्कनेक्ट' आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक और श्रम अधिकार के रूप में चर्चा का विषय बन गया है। मोबाइल फोन, ई-मेल, मैसेजिंग एप और आनलाइन मीटिंग्स ने कार्यस्थल की सीमाओं को लगभग समाप्त कर दिया है। अब काम केवल कार्यालय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि घर, यात्रा और निजी समय में भी प्रवेश कर गया है। इस स्थिति ने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डाला है, जिससे 'राइट टू डिस्कनेक्ट' की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। राइट टू डिस्कनेक्ट का अर्थ है कि किसी कर्मचारी को कार्य समय के बाद कार्यालय से जुड़े काल, संदेश या ई-मेल का उत्तर देने के लिए बाध्य न किया जाए। यह अधिकार इस सिद्धांत पर आधारित है कि काम के बाद व्यक्ति का समय उसका निजी समय होता है, जिसे विश्राम, परिवार और स्वयं के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। लगातार उपलब्ध रहने की अपेक्षा ने कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बढ़ा दिया है। कार्यस्थल का तनाव अब कार्य समय समाप्त होने के बाद भी बना रहता है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और अवसाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं।

विश्व के कई देशों में इस समस्या को गंभीरता से लिया गया है। फ्रांस, स्पेन और कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने राइट टू डिस्कनेक्ट को कानूनी रूप दिया है। वहां कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कर्मचारी कार्य समय के बाहर डिजिटल माध्यमों से काम के दबाव में न रहें। इन कानूनों का उद्देश्य उत्पादकता को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्य संतुलन को बेहतर बनाना है।

भारत में यह अवधारणा अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन तेजी से बदलती कार्य संस्कृति के कारण इस पर बहस तेज हो गई है। आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था नई चुनौतियां पेश कर रही है। राइट टू डिस्कनेक्ट को लेकर स्पष्ट नीति का अभाव कर्मचारियों को असुरक्षित स्थिति में डाल देता है। राइट टू डिस्कनेक्ट केवल कर्मचारियों का अधिकार नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और टिकाऊ कार्य संस्कृति की आवश्यकता है। यह नियोक्ताओं को भी यह समझने का अवसर देता है कि लगातार काम करवाने से दीर्घकालिक उत्पादकता नहीं बढ़ती। मानसिक रूप से संतुलित कर्मचारी ही संस्थानों को मजबूत बनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस विषय पर गंभीर संवाद हो, नीतिगत पहल की जाए और कार्य संस्कृति में यह स्वीकार किया जाए कि विश्राम भी काम जितना ही आवश्यक है। राइट टू डिस्कनेक्ट अंततः मानव गरिमा, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन के अधिकार से जुड़ा प्रश्न है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

तय हो जवाबदेही

विख्यात फुटबालर लियोन मेसी का कोलकाता दौरा, जो बंगाल के लिए गौरव का क्षण हो सकता था, अब प्रशासनिक विफलता और तीखी राजनीतिक जंग का अखाड़ा बन गया है। साल्टलेक स्टेडियम में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में हुई भारी चूक ने न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शहर की छवि को धूमिल किया, बल्कि हजारों दर्शकों को निराश और आक्रोशित कर दिया। आयोजक शताद्रु दत्ता की गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जांच समिति के गठन के बावजूद विवाद थमता नहीं दिख रहा। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर राज्य के खेल मंत्री अरूप बिश्वास और अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। भाजपा का स्पष्ट दावा है कि शताद्रु को बलि का बकरा बनाया गया है। यह आरोप लग रहा है कि सरकार वास्तविक दोषियों यानी वरिष्ठ मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को बचाने के लिए जल्दबाजी में दिखावटी कार्रवाई कर रही है। सुवेंदु ने इसे सारधा चिटफंड घोटाला और आरजी कर कांड जैसी घटनाओं से जोड़ते हुए कहा है कि यह मुख्यमंत्री की पुरानी रणनीति है, जिसमें बड़े लोगों को बचाकर छोटे प्यादों को फंसाया जाता है। यह घटना अब केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। क्या राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय आयोजनों को सुचारु रूप से संचालित करने में सक्षम है? मेसी विवाद ने राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप की नई बहस छेड़ दी है।

> यह आरोप लग रहा है कि सरकार वास्तविक दोषियों को बचाने के लिए जल्दबाजी में दिखावटी कार्रवाई कर रही है

Dainik Jagaran Page No-8

स्थापित करने होंगे जवाबदेही के मानदंड

विवेक काटजू

इंडिगो की सेवाओं में गतिरोध से न केवल लाखों हवाई यात्रियों को पीड़ा पहुंची, बल्कि इससे भारत की छवि पर भी आघात हुआ

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस का परिचालन इस महीने की शुरुआत में ऐसा लड़खड़ाया कि अभी तक कुछ समस्याएं कायम हैं। विमानन बाजार में करीब 65 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली कंपनी की उड़ानों में देरी और उनके रद होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ना स्वाभाविक था। हालांकि अब कुछ स्थिति सुधरी है, पर पूर्ण राहत अभी दूर है। सेवाओं में इस गतिरोध से न केवल लाखों हवाई यात्रियों को पीड़ा पहुंची, बल्कि इससे भारत की छवि पर भी आघात हुआ। सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए इंडिगो पर कार्रवाई भी की है। यह तो जांच में सामने आएगा कि इस अराजकता के क्या कारण रहे, किंतु प्रथमदृष्टया पायलटों के लिए अधिक विश्राम संबंधी नियमों की पूर्ति के लिए अपेक्षित प्रयास न करने को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। कंपनी के पास पायलटों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय था, पर वह बैठी रही।

इंडिगो प्रकरण में एक प्रश्न यह भी उभरा है कि कंपनियों के मामले में सरकार को आखिर कब हस्तक्षेप करना चाहिए? समस्याओं के पहले या उनके उत्पन्न होने के बाद? विशेषकर तब जब उनकी लापरवाही से जनता और देश को नुकसान पहुंचने की आशंका हो। यह प्रश्न राजनीतिक जवाबदेही की ओर भी ले जाता है। यह मुद्दा किसी विशेष सरकार या पार्टी से संबंधित नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक वर्ग और भारत की राजनीतिक संस्कृति से संबंधित है। हमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी पीएसयू और निजी कंपनियों की प्रकृति एवं स्वरूप में अंतर को भी समझना होगा। पीएसयू सरकारी स्वामित्व में होती हैं। उनकी जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों और विभागों की होती है। संबंधित मंत्री के माध्यम से सरकार इन सार्वजनिक कंपनियों को लेकर संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। निजीकरण से पहले विमानन में सरकारी कंपनी की ही अनुमति थी। तब एयरलाइंस ने अपने परिचालन को लेकर ऐसी लापरवाही दिखाई होती तो नागरिक उड्डयन मंत्री को संसद में प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता।

यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का वास्तविक संचालन-प्रबंधन भी खोटी पेशेवरों द्वारा किया जाता है और संबंधित मंत्रियों से अपेक्षा नहीं की जाती कि वे रोजमर्रा के कामकाज में हस्तक्षेप करें। हालांकि, यह सुनिश्चित करना उनका राजनीतिक कर्तव्य है कि वे इसके लिए उचित व्यवस्था बनाएं। इस क्रम में वे वरिष्ठ लोकसेवकों को दायित्व सौंपते हैं। संबंधित लोक सेवकों को इन कंपनियों की स्थिति के बारे में सूचित रखना होता

इंडिगो एयरलाइंस का परिचालन लड़खड़ाने से बढ़ी यात्रियों की परेशानी। फाइल

है। उनकी ओर से किसी भी उभरती समस्या के बारे में चेतावनी दी जाए। ऐसी संभावित समस्या जिससे लोगों के हित प्रभावित हो सकते हों। ऐसे में, मंत्री यह बहाना नहीं बना सकते कि लोक सेवक उन्हें अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि यह भी मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वे उचित लोक सेवकों का चयन करें जो अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाएं। कुल मिलाकर, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के मामले में सरकार और संबंधित मंत्रियों की संसद के प्रति और उनके माध्यम से जनता के प्रति राजनीतिक जवाबदेही सीधी होती है। यह एक अलग मामला है कि कई दशकों से राजनीतिक वर्ग ने हमेशा प्रशासनिक विफलताओं की जिम्मेदारी लोक सेवकों और प्रबंधकों पर डालने की कोशिश की है।

उदारीकरण के साथ अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। इसका ही परिणाम है कि इंडिगो जैसी भीमकाय कंपनियां उभरीं, जो अपने बाजार के एक बड़े हिस्से पर काबिज होकर उसे नियंत्रित करती हैं। ऐसी स्थिति केवल कुछ कानूनों में परिभाषित आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों तक भी है जो ऐसे कानूनों के अंतर्गत नहीं आते। जैसे कि सीमेंट और बिजली उत्पादन क्षेत्र। इन क्षेत्रों में निजी कंपनियों की विफलता से अर्थव्यवस्था पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बड़ी निजी कंपनियां स्वतंत्र निदेशकों के साथ बोर्ड द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि कंपनियां कानूनों और नियमों के अनुसार संचालित हों। यह स्पष्ट है कि इंडिगो का बोर्ड अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा। चूंकि इन कंपनियों के संचालन में सार्वजनिक हित जुड़े होते हैं, इसलिए ऐसे तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करें कि अधिकारियों को समय पर सूचित किया जाए कि कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं होगा कि कंपनी के प्रबंधन में सरकार का हस्तक्षेप होगा। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि सरकार और कंपनियां दोनों संतुलन के साथ कार्य करें। यह अच्छी बात है कि राजनीतिक वर्ग और उद्योग जगत में इस मोर्चे पर परिपक्वता दिखती है।

नियामकीय संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे इसकी निगरानी करें कि कोई कंपनी नियमों के पालन को लेकर सही दिशा में बढ़ रही है या नहीं। इंडिगो के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए की यही जिम्मेदारी थी। क्या डीजीसीए ने इस पर नजर रखी कि इंडिगो नए नियमों के अनुपालन को लेकर आवश्यक पायलटों की भर्ती के लिए प्रयास कर रही है? क्या उसने मंत्रालय के अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया, जिससे जानकारी और आगे बढ़ती। ये प्रश्न किसी को आलोचना के कठघरे में खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हैं ताकि इंडिगो प्रकरण से सबक सीखकर यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। जवाबदेही के राजनीतिक एवं प्रशासनिक मानदंड तो स्थापित करने ही होंगे।

तेजी से वृद्धि कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में विमानन क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि इंडिगो की मौजूदा समस्याएं उन पहलुओं के समाधान तलाशने की दिशा में उन्मुख करें कि कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा जनता और अर्थव्यवस्था को न भुगतना पड़े। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र विशेष में किसी कंपनी का इतना वर्चस्व न हो जाए कि उसकी समस्याएं पूरे देश को नुकसान पहुंचाएं।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

जागरण विशेष

तिरंगे झंडे के पुनर्चक्रण के साथ करते हैं पर्यावरण संरक्षण भी

प्रदीप शर्मा ● जागरण

सेवानिवृत्त मेजर जनरल की पहल से आठ करोड़ राष्ट्रीय ध्वज का पानीपत में हो रहा पुनर्चक्रण

पानीपत: 'हर घर तिरंगा अभियान' के बाद से देश में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग बढ़ा है। ऐसे में गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस समेत कई कार्यक्रमों के बाद झंडे का सम्मानजनक निष्पादन एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। हरियाणा के पानीपत में इसकी पहल हुई और अब सालाना छोटे-बड़े करीब आठ करोड़ राष्ट्रीय ध्वज का री-साइकल (पुनर्चक्रण) सम्मानजनक तरीके से हो रहा है।

इसके साथ ही सेना की इस्तेमाल हो चुकी बुलेट प्रूफ जैकेट व प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज का पुनर्चक्रण कर ऐसे दस्तानों का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें धारदार हथियार से भी नहीं काटा जा सकता। कपड़े के ध्वज से धागा बना दोबारा राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जा रहा है। यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि देशवासियों के तिरंगे के प्रति सम्मान और राष्ट्र प्रेम का भी जीवंत उदाहरण है।

इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत सेवानिवृत्त मेजर जनरल असीम कोहली के सोच से हुई। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के इस्तेमाल के बाद कार्यक्रम स्थल या फिर सड़कों के किनारे पड़े ध्वज देखकर उनका मन खिन्न होता था। असीम कोहली ने तीन साल पहले सेवानिवृत्ति के बाद एक एनजीओ 'सेवाज निसीम' बनाया। इसके माध्यम से पुराने झंडों को एकत्रित करने का काम किया और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) की मदद से आइआइटी दिल्ली से संपर्क किया।

आइआइटी दिल्ली की टीम और अटल सेंटर आफ एक्सीलेंस पानीपत से हाथ मिलाया। पुनर्चक्रण के लिए पानीपत के बलाना में स्थित शिवालिक रज्ज कंपनी को जिम्मेदारी दी गई। इन संस्थानों के विशेषज्ञों ने झंडों में प्रयुक्त फैब्रिक, उनके रासायनिक गुणों और पुनर्चक्रण पर शोध किया। नतीजा यह रहा कि देश में पहली बार सम्मानजनक, वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से प्रमाणित माडल विकसित हुआ।

दो लाख राष्ट्रीय ध्वज से शुरुआत, अब जुड़ेंगे कारपोरेट

असीम कोहली

सेवानिवृत्त मेजर जनरल असीम कोहली ने सेना में लगभग 36 वर्षों तक सेवा दी है। वह बताते हैं कि जब उन्होंने यह मिशन शुरू किया, तब सिर्फ दो लाख राष्ट्रीय ध्वज का पुनर्चक्रण करना भी बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले उनके एनजीओ ने देशभर के आर्मी कैंप से झंडे एकत्रित करने शुरू किए। बाद में टीम ने इसे फ्लैग इंडिया प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया। इस पूरे कार्यक्रम को देशव्यापी बनाने के लिए इंडस्ट्री के साझेदारों और कई कारपोरेट संस्थानों से बातचीत चल रही है। कई आर्मी कैंप में ऐसी व्यवस्था की गई है, जहां इस्तेमाल राष्ट्रीय ध्वजों को एकत्रित किया जाए और फिर उनको कंटेनर की मदद से पानीपत पहुंचाया जाए।

पानीपत के बलाना गांव के पास लगी फैक्ट्री, जिसमें झंडों के पुनर्चक्रण के लिए लगाई गई मशीनें ● जागरण

यह सम्मान की बात है कि राष्ट्रीय ध्वज के पुनर्चक्रण के लिए हमें चुना गया है। हमें पता है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान क्या होता है और इसी सोच व सावधानी के साथ हम प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। **राजेंद्र लीखा**, संचालक, शिवालिक रज्ज पानीपत

इस तरह होता है झंडे का निष्पादन

पानीपत स्थित शिवालिक रज्ज फैक्ट्री में राष्ट्रीय ध्वज का पुनर्चक्रण करने की प्रक्रिया विज्ञानी ढंग से होती है।

पहला चरण: पुराने ध्वजों को अलग-अलग कर उनकी अलग-अलग लेयर बनाई जाती है।

दूसरा चरण: कपड़े और फैब्रिक के ध्वज अलग-अलग किए जाते हैं। फैब्रिक को तोड़कर उच्च गुणवत्ता का यार्न बनता है।

तीसरा चरण: यार्न से पुनः कपड़ा तैयार किया जाता है।

चौथा चरण: इस कपड़े को राष्ट्रीय ध्वज पुनर्निर्माण व विभिन्न उत्पादों में उपयोग किया जाता है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

Dainik Jagaran Page No-6

उद्योगपतियों के प्रति रवैया बदले विपक्ष

प्रो. अमिताभ श्रीवास्तव

ट्रंप टैरिफ वार को नाकाम करने में उद्यमियों का भी योगदान रहा है, जो दुर्भाग्य से विपक्ष के निशाने पर रहे हैं

अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते उद्योगपति। फाइल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय धान पर टैरिफ लगाने की परोक्ष धमकी देकर भारत को डराने की फिर कोशिश की है, पर तथ्य इस बात के गवाह हैं कि ट्रंप प्रशासन स्वयं डरा हुआ है। पचास प्रतिशत टैरिफ का ट्रंप कार्ड 'जोकर' साबित हो चुका है। इसका क्रेडिट काफी हद तक भारतीय उद्योगपतियों को जाता है, जो दुर्भाग्य से अपने ही देश में विपक्ष के हमलों का शिकार हो रहे हैं। मौजूदा विश्व अर्थव्यवस्था में हर देश अपने उद्योगपतियों को मूल्यवान समझता है। याद कीजिए लगभग तीन दशक पहले गेट यानी जनरल एग्रीमेंट आन टैरिफ एंड ट्रेड के जरिए भारत समेत विकासशील देशों पर दुनिया भर में टैरिफ कम करने का दबाव डाला गया था। आज अमेरिका खुद उसी टैरिफ की आड़ ले रहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून का उल्लंघन हो रहा है। घरेलू मोर्चे पर एलन मस्क जैसे बड़े उद्योगपति ट्रंप से मुंह मोड़ चुके हैं। ट्रंप के दबाव के बावजूद हाल में माइक्रोसाफ्ट और गूगल ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की है, पर लाख टके की बात यह है जब तक हम अपने उद्योगपतियों को ताकत नहीं देते, विकसित देशों के उद्योगपतियों से मुकाबला कठिन है।

हाल में रूसी प्रतिनिधिमंडल में तेल और ऊर्जा क्षेत्र के रोसनेफ्ट, स्बेयर बैंक, यूरिया उत्पादन से जुड़ी यूराल नेट, हथियार उत्पादन के लिए मशहूर रोजोबारोनेक्सपोर्ट जैसी कंपनियों के आला अधिकारी आए थे। वहीं भारत की ओर से टाटा, अंबानी, अदाणी किसी की भी रूसी प्रतिनिधिमंडल से सीधी बात नहीं हुई। ऐसा नहीं कि सीधी बात न होने से भविष्य में व्यापार की सारी संभावनाएं ही समाप्त हो गई हों, पर साफ है कि रूसी राष्ट्रपति की मौजूदगी में भारत की प्रमुख कंपनियों की उपस्थिति एक सकारात्मक असर डालती। यह अवसर हम चूक गए। शायद नीति निर्धारकों का सोच यह रहा हो कि कुछ अहम समूहों की उपस्थिति सियासी विवाद को जन्म देती और संसद सत्र के दौरान सरकार कोई मुद्दा विपक्ष को देने को तैयार नहीं थी।

जरा सोचिए कि अफगानिस्तान में आतंक के दौरान भारतीय कंपनियों ने किन परिस्थिति में कार्य किया होगा और भारत सरकार ने तब उन्हें संरक्षण देकर सही किया या गलत? और आज फार्मा से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में निजी कंपनियों को अफगानिस्तान में भेजा जाना क्या जरूरी नहीं है? अफगानिस्तान ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, अफ्रीका आदि देशों में अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों से सहयोग लिया और आवश्यक संरक्षण प्रदान किया। घरेलू मोर्चे पर भी संकट के समय वैक्सीन का अतिरिक्त उत्पादन हो या ऊर्जा संकट के दौर में वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर, सभी कुछ निजी कंपनियों के जरिए हासिल किया गया, पर कभी तीन सौ तो कभी तीन व्यावसायिक समूहों के नाम पर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। भले स्वशासित राज्यों में उद्योगपतियों को महत्व देने के लिए खुलेआम भ्रष्टाचार तक का सहारा लिया गया हो। विपक्ष के नेता को वैचारिक खाद-पानी दे रहे एक वामपंथी नेता के पुत्र रियल स्टेट और बिस्किट फैक्ट्री के क्षेत्र में बंगाल के बड़े उद्योगपति बने। उनके उत्थान का काल सबसे लंबे दौर तक बंगाल में चला पिता जी का कार्यकाल ही रहा। उनकी ईस्टर्न बिस्किट कंपनी पर भी 37.68 लाख रुपये बकाये का केस बना। अदालत ने अन्य अपेक्षाओं के साथ पंद्रह लाख रुपये की बैंक गारंटी का आदेश दिया, जो नहीं भरी गई। बाद में अंतरिम आदेश रद हो गया। फाइल वर्षों बाद 2005 में मिली।

आज वामपंथ के असर से मुक्ति पाकर बड़ी मुश्किल से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत ने तमाम कामयाबी हासिल की है। जापान पिछड़ चुका है और अब जर्मनी की बारी है, लेकिन सच यह भी है भारत की अर्थव्यवस्था जहां अब तक पांच ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर का आंकड़ा नहीं छू पाई है वहीं अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्थाएं तीस और बीस ट्रिलियन डालर से ऊपर की हो चुकी हैं। यानी अभी काफी कुछ किया जाना है, क्योंकि दुनिया आकाश से आई आवाज ही सुनती है। ताकतवर प्रतिद्वंद्वियों के साथ क्या करते हैं यह पहले चीन और फिर ट्रंप के बर्ताव से साफ है। दुनिया में आवाज शिखर की सुनी जाती है। बाकी आवाज या तो दब जाती है या उन आवाजों का दम घोंटने की कोशिश की जाती है।

ट्रंप का मौजूदा रूप आपको यकीनन अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यह भी है कि ट्रंप से पहले भी समय-समय पर अमेरिका ने इसी तरह से भारतीय हितों में बाधा डालने का प्रयास किया था। यह बात अलग है कि डरावने नाखूनों वाले शरीर पर तब नफासत की नकाब लगी थी। याद कीजिए वह दौर जब भारतीय कपड़ों की खेप को यह कह कर लौटाया गया था कि इसमें आग लग जाती है। फलों की खेप कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग कह कर लौटा दी जाती थी, पर जब अमेरिकी पेय पदार्थों में कीटनाशकों का मामला आया तो पूरा अमेरिका प्रशासन मोर्चा संभालने लगा। जिस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी मोटर साइकिल कंपनी के हित को अपने देश का हित बता रहे हों, उस दौर में भारत के व्यवसायियों के वाजिब हितों के लिए कौन लड़ेगा? समाज और राजनीति, दोनों को व्यापार जगत के अपने योद्धाओं यानी उद्योगपतियों के प्रति रवैया बदलना होगा। ध्यान यह भी रहे व्यवसायियों को भी समाज के प्रति अपने दायित्व का पालन करना होगा।

(लेखक राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान संकाय के अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

हां 86% नहीं 14% — क्या उड्डयन क्षेत्र में इंडियो के एकाधिकार का खामियाजा लाखों यात्रियों को भुगतना पड़ा?

हां 75% नहीं 25% — क्या एकाधिकार को रोकने के लिए बनाया गया नियामक तंत्र अप्रभावी साबित हुआ?

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया mudda@jagran.com पर भेज सकते हैं।

दो दिसंबर की सुबह हजारों यात्री एयरपोर्ट पर थे। उनको अपनी मंजिल पर पहुंचना था, लेकिन पता नहीं था कि वह कब पहुंचेंगे, क्योकि उनकी फ्लाइट रद हो गई थी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। लोगों को 10-10 घटें तक फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा। लाखों यात्रियों को बेबस होकर मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ा। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। पूरे देश में अफरातफरी का माहौल बन गया था। इसकी वजह यह थी कि देश में प्रत्येक 10 हवाई यात्रियों में से छह इंडिगो की फ्लाइट में यात्रा करते हैं और इंडिगो एयरलाइंस का कामकाज बाधित हो गया था। किसी सेक्टर में एक कंपनी या संस्था का एकाधिकार किस तरह के नतीजे दे सकता है, इंडिगो संकट इसकी एक बानगी है। देश के उड्डयन बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी करीब 65 प्रतिशत है, वहीं दूसरी बड़ी कंपनी एअर इंडिया की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत। यह एकाधिकार रातोंरात नहीं हुआ। सवाल है कि नियामक संस्थाओं ने समय पर इस खतरे को पहचान कर इसे दूर करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? देश के उड्डयन बाजार में एकाधिकार की स्थिति कैसे बनी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी पड़ताल अहम मुद्दा है...

एकाधिकार का दंश

क्या है एकाधिकार

एकाधिकार एक ऐसी बाजार स्थिति है, जहां किसी एक कंपनी का किसी वस्तु या सेवा पर पूरा नियंत्रण होता है, कोई करीबी विकल्प नहीं होता, जिससे कंपनी अपनी मर्जी से कीमतें तय कर सकती है। इसके नुकसानों में उपभोक्ताओं के लिए ऊंची कीमतें, घटिया गुणवत्ता, और नवाचार की कमी शामिल हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती, जिससे उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुंचता है और बाजार में अनुचित व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।

दो कंपनियों का प्रभुत्व

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का व्यस्त उड़ान शेड्यूल नवंबर में उस समय बिगड़ गया, जब पायलट और क्रू मेंबर्स को ज्यादा आराम देने वाला नया नियम लागू हुआ। दिसंबर के पहले हफ्ते में एयरलाइन पूरी तरह बिखर गई। एक दिन में ही 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद कर दी गईं। इससे 10 लाख से ज्यादा बुकिंग प्रभावित हुईं। लोग परेशान हुए और हालात बिगड़े तो सरकार ने एयरलाइन की कार्यप्रणाली की जांच का आदेश दिया। बड़ा सवाल यह है कि महज एक कंपनी की गड़बड़ी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन सेक्टर कैसे ठप हो सकता है? इसका जवाब बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी होने में छिपा है। दरअसल 2007 में शुरू हुई इंडिगो की जबरदस्त कामयाबी ने उसे घरेलू उड्डयन बाजार का 64 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा दे दिया। वहीं एअर इंडिया के पास 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इंडिगो संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था में एकाधिकार के खतरों को सामने ला दिया है। यहां एयरलाइंस से लेकर टेलीकाम और यूपीआइ से लेकर ई- कामर्स तक में ज्यादातर बाजार हिस्सेदारी कुछ ही कंपनियों के पास है। हालांकि विशेषज्ञों और और नियामकों का कहना है कि किसी सेक्टर में एक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी ज्यादा होना ही अपने आप में समस्या नहीं है। हालांकि अगर प्रभुत्व वाली कंपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को बाजार से बाहर करवा देती है या उपभोक्ताओं का शोषण करती है तो इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यहां पर सरकार को दखल देना चाहिए।

एयरपोर्ट और ईंधन रिफाइनिंग पर दो कंपनियों का है कब्जा

इंडिगो का बुरा हफ्ता भारत की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी समस्या को उजागर करता है। यहां सबसे बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को बाहर कर रही हैं। हवाई क्षेत्र में इतनी कम प्रतिस्पर्धा और कुछ ही कंपनियों के हाथ में इतना ज्यादा नियंत्रण अब भारत में आम हो गया है। भारत के सबसे फायदेमंद एयरपोर्ट दो कंपनियां चलाती हैं और देश के 40 प्रतिशत ईंधन की रिफाइनिंग भी दो कंपनियां करती हैं। इनके अलावा दूरसंचार, ई-कामर्स, बंदरगाह और स्टील जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी कुछ ही बड़ी कंपनियां हावी हैं।

बाजार में दो कंपनियों का दबदबा

(हिस्सेदारी प्रतिशत में)

सेक्टर	पैरामीटर	कंपनियां		शीर्ष दो कंपनियों की हिस्सेदारी	शीर्ष तीन कंपनियों की हिस्सेदारी	शीर्ष पांच कंपनियों की हिस्सेदारी
डिपाजिटरी	सक्रिय ग्राहक खाते	सीडीएसएल	एनएसडीएल	100	-	-
एयरलाइंस (घरेलू)	यात्री, दूरी	इंडिगो	एयरइंडिया	91	96	100
यूपीआइ	लेनदेन का मूल्य	फोन पे	गूगल पे	84	90	94
टेलीकाम	मोबाइल ग्राहक	जियो	एयरटेल	75	92	100
एयरपोर्ट	यात्रियों की संख्या	अदाणी	जीएमआर	64	87	100
डीटीएच	ग्राहकों की संख्या	टाटा प्ले	एयरटेल	60	81	100

टेलीकाम मार्केट में भी तीन कंपनियों का ही वर्चस्व

आठ महीने पहले भारत की दो बड़ी दूरसंचार कंपनियों जियो और एयरटेल के पीछे तीसरी कंपनी वोडाफोन आइडिया थी, जो सरकार को दिए जाने वाले टैक्स के बोझ से दबी थी। मार्च में सरकार ने उस कर्ज का बड़ा हिस्सा अपनी हिस्सेदारी में बदल दिया और अब सरकार का कंपनी में 49 प्रतिशत हिस्सा है। आज की स्थिति देखकर साफ है कि भारत में कम से कम तीन नेशनल टेलीकाम कंपनियां बनी रहेंगी। हालांकि वोडाफोन आइडिया अभी भी बकाया शुल्क नहीं चुका पाई है।

प्रतिस्पर्धा आयोग के पास सीमित शक्तियां

भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस साल पहली बार पाया कि 8 बड़े सेक्टर्स में बड़ी कंपनियों का एकाधिकार है। लेकिन आयोग के पास सिर्फ संभावित विलय की जांच करने और उसे मंजूर या खारिज करने की ताकत है। कंपनियों के आकार में बढ़ोतरी रोकने या उड्डयन जैसे उद्योगों में एकाधिकार कम करने की ताकत उसके पास नहीं है। भारत में कभी प्रतिस्पर्धी बाजार का माडल नहीं रहा, इसीलिए इसके खिलाफ एक्शन को लेकर भी बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है।

नई कंपनियों को नहीं मिलता आसानी से कर्ज

नई कंपनियों के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्रेडिट यानी कर्ज न मिलना है। 2015 के आसपास एनपीए संकट सामने आने के बाद बैंक सिर्फ सबसे ताकतवर कंपनियों को ही कर्ज दे रहे हैं। बड़ा होना आपको सफल होने की ज्यादा संभावना देता है जैसा कई देशों में होता है। लेकिन भारत में बड़ी कंपनियों की कर्ज लेने की ताकत निर्णायक है।

जागरण रिसर्च

प्रभुत्व का फायदा न उठाने दे सीसीआइ

केके शर्मा
पूर्व महानिदेशक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सीसीआइ को एक मार्केट वाच डिवीजन बनाना चाहिए, जो बाजार पर नजर रखे और ऐसे हालात ही पैदा न होने दे, जहां कोई कंपनी अपनी मजबूत बाजार स्थिति का दुरुपयोग कर सके। इसी तरह से भविष्य में इंडिगो संकट जैसे हालात को रोका जा सकता है।

पूरी दुनिया में देखा गया है कि जिन सेक्टरों में ज्यादा निवेश की जरूरत होती हैं, वहां दो तीन बड़ी कंपनियां ही होती हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में भी ऐसा हो रहा है। जैसे उड्डयन या टेलीकाम को ले लें। यहां किसी नए प्लेयर के लिए आना और खुद का बाजार में स्थापित करना आसान नहीं है क्योंकि यहां कारोबार शुरू करने के लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत है। अगर किसी सेक्टर में दो कंपनियां हैं और उनकी बाजार हिस्सेदारी 55:45 के अनुपात में है, तो यह बेहतर स्थिति है। इससे दोनों कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है और इससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होता है। वहीं अगर किसी सेक्टर में एक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है और दूसरी की 30 प्रतिशत तो यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। हाल में इंडिगो संकट में इस खतरनाक स्थिति को देखा जा सकता है क्योंकि वर्तमान में भारत के उड्यन क्षेत्र में इंडिगो की हिस्सेदारी करीब 65 प्रतिशत है और एअर इंडिया की हिस्सेदारी काफी कम है। इस संकट के दौरान इंडिगो के व्यवहार को निश्चित रूप से बाजार में अपनी स्थिति के दुरुपयोग के बजाए बाजार की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से कंपनी का रवैया एकाधिकार वाला रहा है।

कंपनी के व्यवहार से साफ संकेत मिलता है कि उसे लग रहा था कि कोई उसका क्या कर सकता है क्योंकि उड्डयन सेक्टर में दो कंपनियों का ही प्रभुत्व है। 2009 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) के महानिदेशक के तौर पर मेरे कार्यकाल के दौरान उड्डयन क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों ने एटीएफ की कीमतों को लेकर सरकार को धमकी दी थी कि 15 दिन के बाद कोई भी जहाज नहीं उड़ेगा। उस दौरान सीसीआइ ने इस संबंध में खतरे को लेकर सरकार को अलर्ट किया था और इस की जांच के लिए एक नोट भी बनाया था। हालांकि, कुछ वजहों से यह मामला आगे नहीं बढ़ सका।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 बाजार में प्रभुत्व वाली स्थिति के लिए सिर्फ बाजार हिस्सेदारी के आधार पर कोई साफ संकेत नहीं देता है। इस अधिनियम के तहत प्रभुत्व वाली स्थिति ज्यादा बारीक है और अधिनियम के सेक्शन 19(4) में यह सिर्फ बाजार हिस्सेदारी पर नहीं, बल्कि 13 फैक्टर्स से तय होती है। हालांकि, इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 65 प्रतिशत के करीब होने और दूसरे प्लेयर एअर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी सिर्फ 25 प्रतिशत होना उड्डयन बाजार के लिए बुरी खबर है। एयर इंडिया का ज्यादातर विस्तार इंटरनेशनल रूट पर होने के कारण, घरेलू उड्डयन बाजार पूरी तरह से इंडिगो की ओर झुका हुआ है। आम तौर पर डुओपोली यानी दो कंपनियों के प्रभुत्व वाली में स्थिति में दोनों कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी में 10-15 प्रतिशत से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। 40-55 प्रतिशत की डुओपोली में कंपनियां के बीच प्रतिस्पर्धा होती है और कंपनियां एक दूसरे को नियंत्रित करती हैं। दूसरी ओर, अगर एक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है और दूसरे की बाजार हिस्सेदारी 15 प्रतिशत तो यह सिर्फ नाम की डुओपोली है, और इसमें एकाधिकार के लक्षण दिखने की संभावना है। यह आज के भारतीय उड्डयन बाजार की स्थिति के बहुत करीब है। हालांकि, किसी भी जांच में ऐसा घोषित नहीं किया गया है लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, इंडिगो न केवल प्रभुत्व वाली स्थिति में है, बाजार में असल में एक एकाधिकार वाली कंपनी है। इंडिगो संकट का सीधा कारण डीजीसीए द्वारा सख्ती बरतना है क्योंकि इंडिगो दो साल से जरूरी सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर रही थी। इससे भी ज्यादा जरूरी यह देखना है कि स्थिति यहां तक कैसे पहुंची। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इंडिगो एकाधिकार वाली वाली कंपनी थी और उसे यह गलतफहमी थी कि वह 'इतनी बड़ी है कि उसे फेल नहीं होने दिया जा सकता'। अगर ऐसा नहीं होता तो वह मुनाफे के लिए सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं करती और जरूरी संख्या में पायलटों की भर्ती करती। यह बात सेक्टर रेग्युलेटर डीजीसीए के अस्थायी रूप से पीछे हटने से भी कुछ हद तक सच साबित होती है। आम तौर पर नए पायलटों की भर्ती और ट्रेनिंग में छह महीने तक लग सकते हैं।

डीजीसीए द्वारा तय सुरक्षा नियमों का पालन न करना एक एकाधिकार वाली कंपनी के घमंड को दिखाता है, जिसे लगता है कि उस पर अनुशासन लागू करने से उड्डयन बाजार में बड़ी दिक्कतें आएंगी। इसलिए, यह दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग नहीं है, बल्कि यह ऐसे बाजार में जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रभुत्व वाली कंपनी के लगातार दबदबे वाली स्थिति का नतीजा है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) को मार्केट वाच डिवीजन बनाना चाहिए, जो ऐसी कंपनियों पर नजर रखे जो बाजार में अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर सकती हैं और ऐसे हालात पैदा होने से रोकने के लिए समय से कदम उठाए।

कंपनी की बाजार हिस्सेदारी ज्यादा होना खतरा नहीं

एसएस मणि
पार्टनर, डेलाइट

किसी सेक्टर में एक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी अधिक होना ही अपने आप में खराब बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि कंपनी अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग ही करेगी। यहां पर नियामकीय तंत्र को सतर्क रहना चाहिए कि कंपनी बाजार में प्रभुत्व का दुरुपयोग न कर पाए।

आम तौर पर किसी भी सेक्टर में चार पांच प्लेयर होने चाहिए। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा रहती है और इसका फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलता है लेकिन भारत में मौजूदा परिदृश्य की बात करें तो यहां हालात अलग नजर आते हैं। इसकी वजह यह है कि जिन सेक्टर में बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत है, वहां नए प्लेयर के लिए घुसना बहुत कठिन है।

जैसे अगर आप टेलीकाम सेक्टर को ले लें। इस सेक्टर में किसी प्लेयर को अगर काम शुरू करना है तो उसे लगभग 30,000 करोड़ रुपये चाहिए। पहले से टेलीकाम सेक्टर में जो प्लेयर हैं वह मुश्किल से पांच प्रतिशत मुनाफे पर काम कर रहे हैं। अब अगर किसी के पास 30,000 करोड़ रुपये हैं तो वह ऐसे सेक्टर में क्यों जोखिम लेगा जहां शुरुआती निवेश बहुत अधिक है और मुनाफा बहुत कम। सिर्फ निवेश की बात नहीं है एक नए प्लेयर के लिए बाजार में घुसना और खुद को स्थापित करना एक और चुनौती है। इसके बजाए वह 30,000 करोड़ कर्ज देकर आठ प्रतिशत ब्याज हासिल कर सकता है। किसी भी सेक्टर में चार पांच प्लेयर का होना अच्छी बात है लेकिन यह कई बार यह व्यावहारिक नहीं होता है। इसी तरह से एविएशन सेक्टर में अगर कोई नया प्लेयर आना चाहता है तो वह चार पांच विमान से काम शुरू नहीं कर सकता है। इसके लिए डीजीसीए ने जो न्यूनतम जरूरत तय की है, उसके तहत किसी नई कंपनी के पास सेक्टर में काम शुरू करने के लिए 12 विमान होने चाहिए। इसके अलावा दूसरे जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करना होगा। इसके लिए कम से कम पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। इसके बाद बात आती है कि वह विमान कहां से लेगा। इस समय दुनिया में सिर्फ दो ही कंपनियां विमान बनाती हैं।

एक है अमेरिका की बोइंग और दूसरी फ्रांस की एयरबस। इन दोनों कंपनियों के पास पहले से अगले पांच वर्ष के लिए आर्डर बुक हैं। अगर कोई नई कंपनी इन कंपनियों को पूरा भुगतान करती है तो उसे विमान तीन वर्ष बाद मिलने शुरू होंगे। इसका मतलब है कि भारत के एविएशन सेक्टर में किसी नए प्लेयर को काम शुरू करना है तो उसे कम से कम तीन वर्ष इंतजार करना होगा। इसके बाद दूसरी चुनौतियां हैं कि उसे कितने रीजन और कितने रूट मिलेंगे। यहां चुनौती बाजार मांग की भी है। भारत में जहां पर वंदेभारत ट्रेन शुरू हुई हैं, उन रूट पर हवाई जहाज से यात्रा करने वाले ट्रेन पर शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रेन से यात्रा करना प्लेन की तुलना में सस्ता और आरामदायक है।

वहां आपको फ्लाइट टाइम से दो घंटे पहले नहीं पहुंचना है। ऐसी बहुत सी व्यावहारिक दिक्कते हैं। दुनिया के दूसरे देशों को देखें तो यूरोप में चार और अमेरिका में पांच एयरलाइन हैं। यूरोप और अमेरिका में हवाई यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह बहुत अधिक नहीं है। अगर इंडिगो संकट की बात करें तो यह साफ दिखता है कि कंपनी ने बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग किया है। इसके लिए नियामकीय तंत्र जिम्मेदार है। किसी कंपनी का बाजार में प्रभुत्व होना खराब बात नहीं है खराब बात उसका अपनी मजबूत स्थिति का बेजा इस्तेमाल करना है। इस पर नियामकीय तंत्र को ध्यान देना चाहिए।

आपकी आवाज

नियामक तंत्र के फेल होने के कारण ही इंडिगो एयरलाइंस में लापरवाही हुई, ऐसी लापरवाही तो बहुत से लोगों की जान पर भी भारी पड़ सकती है। केंद्र सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती न हो। प्राइवेट संस्थानों से उम्मीद होती है कि यह हमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए हम ज्यादा पैसा भी खर्च कर देते हैं, लेकिन हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस की लापरवाही ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इंडिगो के कारण यात्रियों को जो परेशानी हुई उसकी उचित और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। — राजेश चौहान

उड्डयन क्षेत्र में इंडिगो के एकाधिकार और लापरवाही का नतीजा यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। कोई भी कंपनी अपने बेहतर सेवा, सुविधा और गुणवत्ता के बदौलत उस क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करती है परंतु एकाधिकार के बाद गुणवत्ता में गिरावट और मनमानी के कारण इस तरह की समस्याएं पैदा होती है। इंडिगो यात्रियों को सेवा और सुविधा दोनों देने में विफल रहा है। यह समस्या अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक सबक बन सकती है जहां पर एक ही कंपनी का उस क्षेत्र में एकाधिकार हो। इससे सरकार को सीख जरूर लेनी चाहिए। — देवानंद राय

Dainik Jagaran Page No-7

नई अमेरिकी सुरक्षा नीति में भारत कहां

जोरावर दौलत सिंह | इतिहासकार और रणनीतिकार

अपने स्वार्थ में डूबे अमेरिका की नई सुरक्षा रणनीति में भारत अब भी अहम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस रणनीति में पाकिस्तान की स्थिति और मजबूत हुई है।

उन्नीसवीं सदी के जर्मन राजनेता ओटो वॉन बिस्मार्क ने एक बार कहा था, 'मूर्खों, शराबियों और अमेरिका पर ईश्वर की विशेष कृपा बरसती है।' इससे पता चलता है कि किस्मत ने अमेरिका को क्या दिया है। बड़े सागरों और प्रचुर संसाधनों से भरे महाद्वीप से घिरे होने के कारण अमेरिका थोड़े से भू-राजनीतिक प्रयासों से भी शांति और समृद्धि हासिल कर सकता था। उसके लिए दुनिया के हरेक कोने में अपनी ताकत दिखाना हमेशा से वैकल्पिक रहा है, अनिवार्य नहीं, पर उसकी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) में पश्चिमी गोलार्ध पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की वकालत की गई है और कहा गया है कि ''हम मुनरो सिद्धांत के लिए 'ट्रंप कोरोलरी' को लागू करेंगे''।

ऐसी सुरक्षा रणनीति क्यों बनाई गई है, इसके कारण स्पष्ट हैं। पहला, विश्व में अमेरिका की आगामी भूमिका को लेकर पश्चिमी जगत में भयंकर टकराव चल रहा है, शायद एक तरह का गृहयुद्ध भी। ये मतभेद मामूली नहीं हैं, बल्कि पश्चिमी समाज की राजनीतिक व्यवस्था और राष्ट्रीय पहचान के साथ-साथ विश्व स्तर पर उनकी रणनीतिक भागीदारी से जुड़े हैं। सत्ता-प्रतिष्ठानों के उस दबाव को ट्रंप प्रशासन ने खुले तौर पर चुनौती दी है, जिसके तहत वर्चस्व की विफल रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरह, वैश्विक परिदृश्य भी समान रूप से अहम हैं, क्योंकि इनसे शक्ति संतुलन में ऐसे बदलाव आए हैं, जिनकी कल्पना दो दशक पहले तक नहीं की जा सकती थी। गैर-पश्चिमी देशों और उनके प्रमुख शक्ति-केंद्रों का भरोसा अमेरिकी नेतृत्व से डिगा है। इससे नए सुरक्षा विमर्श पैदा हो रहे हैं। यह असामान्य परिस्थिति ट्रंप और उनके साथियों को पश्चिम की 'व्यापक रणनीति' (अपनी दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए सभी साधनों के इस्तेमाल) में अहम बना देती है।

कुल मिलाकर, अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पश्चिमी गोलार्ध में दबदबा बनाने की वकालत

करती है और यूरोप व एशिया में रणनीतिक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए अमेरिकी गठबंधन के अग्रिम पंक्ति के देशों पर जिम्मेदारियों का 'भार डालने' का प्रस्ताव करती है। चूंकि एनएसएस अमेरिकी गुट की मौजूदा प्रतिबद्धताओं पर मौलिक रूप से सवाल नहीं उठाती या नई सुरक्षा व्यवस्था की बात नहीं कहती (इसमें बहुध्रुवीयता का उल्लेख नहीं है), इसलिए इसे ऐसी भू-राजनीति के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें कोई महाशक्ति अपनी उपस्थिति, सैन्य प्रभाव व विदेश नीति से जुड़ी प्रतिबद्धताओं में तेजी से कमी करती है। इसे दुनिया भर में अमेरिका की प्रमुख स्थिति को कम खर्च करते हुए और शक्तिशाली देशों के साथ संघर्ष से बचते हुए संरक्षित करने की इच्छा के रूप में देखा जाना चाहिए।

यह सोच कुछ हद तक चालाकी भरा प्रतीत होती है और इस उलझन को दो अलग-अलग ढांचों के बीच अनसुलझे संघर्ष से समझा जा सकता है, जो हैं- विश्व व्यवस्था के प्रति 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' की सोच और व्यापक अंतरराष्ट्रीय भूमिका में निहित डीप स्टेट के हित। हालांकि, एनएसएस इस बात को गलत ठहराती है कि अमेरिका में व्यापक पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय प्रभुत्व की वैचारिक जड़ें मौजूद हैं।

एनएसएस साफ करती है कि रूस के साथ नाटो का टकराव विफल रहा और चीन को नियंत्रित करना अब व्यावहारिक नहीं है। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करना, युद्ध के अनपेक्षित विस्तार को रोकना, रूस के साथ रणनीतिक स्थिरता को फिर से कायम करना व नाटो के विस्तार को रोकने में ही अब अमेरिका के 'बड़े हित' हैं। चीन के बारे में यह कहती है कि उसके समुद्री विस्तार को रोकने का प्रयास इस तरह से किया जाए कि संघर्ष से बचा जा सके और 'पारस्परिक रूप से लाभकारी' आर्थिक निर्भरता बनी रहे। चीन को उन्नत एच200 सीरीज के चिप निर्यात करने संबंधी व्हाइट हाउस के फैसले को इसी रणनीति का हिस्सा मानना चाहिए। संघर्ष से बचने का एक अन्य उदाहरण चीन-जापान के बीच पैदा तनाव के दौरान बीजिंग को अमेरिका द्वारा दिया गया हालिया आश्वासन है।

यूरोप के बारे में एनएसएस में कहा गया है कि 'यूरोपीय देशों के भीतर यूरोप की मौजूदा दिशा के प्रति प्रतिरोध पैदा करना होगा'। अमेरिका चाहता है कि यूरोप 'अपने सभ्यतागत आत्मविश्वास को फिर से हासिल करे'। यह काफी हद तक ट्रंप द्वारा घरेलू स्तर पर किए गए पुनर्जागरण के प्रयास जैसा होगा। यदि ये घोषणाएं स्पष्ट नीतियों का रूप ले सकीं, जो यूरोपीय संघ में बची हुई वैश्विक व्यवस्थाओं को कमजोर करती हैं, तो इस सोच का यूरोप की भू-राजनीति और भविष्य में पश्चिमी देशों के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? भारत का संक्षिप्त उल्लेख आश्वस्तकारी संकेत देने के इरादे से किया गया है। फिर भी, संपूर्ण दस्तावेज के संदर्भ और इसके अंतर्निहित वैचारिक व भू-राजनीतिक आधार बताते हैं कि नई दिल्ली यदि पुराने प्रतिमानों पर कायम रही, तो उसे सचेत रहना होगा। एकध्रुवीयता के शीर्ष काल में अमेरिका ने भारत को लेकर जो कल्पना की थी, वह दौर अब बीत चुका है और विश्व स्तर पर बदलता शक्ति समीकरण वास्तविक व स्थायी है।

एनएसएस को इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि भारत अब भी वाशिंगटन के रडार पर मौजूद है, बल्कि यह समझने के लिए इस पर गौर करना चाहिए कि अमेरिका पश्चिमी प्रशांत में चीन के प्रति अपने 'दुश्मन-दोस्त' रवैये में भारत को किन उद्देश्यों के लिए उपयोगी मानता है? निस्संदेह, भारत अब भी अमेरिका के लिए अहम है। हालांकि, इस साल मध्य-पूर्व में अमेरिकी नेतृत्व वाली सुरक्षा व्यवस्था में पाकिस्तान के शामिल होने पर एनएसएस की चुप्पी यही बताती है कि यह उप-महाद्वीप अमेरिका-भारत रिश्ते में टकराव व अनिश्चय का क्षेत्र बन गया है। पाकिस्तान व उसकी सेना के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता, जो पिछली नीति का एक स्थायी कारक है, भू-राजनीतिक स्तर पर मजबूत हुई है, और यह विडंबना है कि इस नीति को अमेरिकी डीप स्टेट का समर्थन हासिल है। इस वजह से यह ऐसा दुर्लभ मसला भी है, जिस पर विभाजित अमेरिका में भी सहमति है।

यह राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति कहती है, 'अमेरिका द्वारा एटलस की तरह पूरी विश्व व्यवस्था को सहारा देने के दिन अब लद गए हैं'। लगता यही है कि बिना साफ तौर पर इसका समर्थन किए, अमेरिका ने बहुध्रुवीय विश्व की जरूरत को मान लिया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

प्रश्न:
भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में एक महत्वपूर्ण संक्रमणकाल से गुजर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP 2020) के आलोक में केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा आयोग *(HECI)* जैसे नियामक ढांचे के प्रस्ताव, बहु-विषयक शिक्षा, गुणवत्ता सुधार और संस्थागत स्वायत्तता पर जोर, उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव का संकेत देते हैं।

इस संदर्भ में, भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में प्रस्तावित सुधारों का **आलोचनात्मक विश्लेषण** कीजिए। अपने उत्तर में निम्नलिखित आयामों को शामिल करें—

1. **पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता:**
   - भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की संरचनात्मक समस्याएँ—नियामक बहुलता, गुणवत्ता असमानता, सीमित शोध संस्कृति और रोजगारोन्मुख कौशल की कमी।
   - वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और जनसांख्यिकीय दबाव के संदर्भ में सुधारों की आवश्यकता।
2. **प्रमुख सुधार पहलें:**
   - राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत बहु-विषयक शिक्षा, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, लचीले पाठ्यक्रम और शोध पर बल।
   - प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग के माध्यम से नियमन, प्रत्यायन, वित्तपोषण और मानक निर्धारण को अलग-अलग स्तंभों में संगठित करने की अवधारणा।
3. **गुणवत्ता सुधार के प्रयास:**
   - संकाय विकास, शोध एवं नवाचार को बढ़ावा, अंतरराष्ट्रीयकरण और डिजिटल शिक्षा की भूमिका।
   - संस्थानों की स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच संतुलन।
4. **संभावित चुनौतियाँ:**
   - केंद्र–राज्य संबंध, संघीय ढांचे में शिक्षा का स्थान।
   - संसाधनों की कमी, क्षेत्रीय विषमता, और निजीकरण से जुड़ी आशंकाएँ।
   - समावेशन, वहनीयता और सामाजिक न्याय से जुड़े प्रश्न।
5. **आगे की राह:**
   - सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नीति, वित्त और संस्थागत क्षमता निर्माण।
   - सार्वजनिक–निजी सहयोग, राज्यों की भागीदारी और सतत निगरानी की आवश्यकता।

निष्कर्ष:
उच्च शिक्षा सुधारों को भारत के ज्ञान-आधारित समाज और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लक्ष्य से जोड़ते हुए संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा: लगभग 400 शब्द)